सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 223, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

महिला आरक्षण व लोकसभा सीट वृद्धि को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?

शुभांगी मिश्रा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को जो तीन ड्राफ़्ट बिल (मसौदा विधेयक) भेजे हैं उनमें दो बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं, पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना और दूसरा, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। इन विधेयकों को 16 से 18 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। ये तीन विधेयक हैं-

केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक 2026, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 (डीलिमिटेशन बिल 2026)। ये 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था।

इसी वजह से, 2023 का ये क़ानून संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद कई लोगों ने चिंता जताई थी कि इस आरक्षण को लागू होने में एक दशक से भी अधिक समय लग सकता है। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं, तो 2029 के अगले आम चुनाव में इस आरक्षण का रास्ता साफ़ हो सकता है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश बताया और इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया।

सबसे तीखी आलोचना लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव को लेकर हो रही है। कई विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई कि सीटों के पुनर्निर्धारण का जो आधार है वो दक्षिणी राज्यों के लोकसभा में प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है। इन तीनों विधेयकों के प्रस्तावों और उनसे जुड़े विवादों को समझें।

1. लोकसभा सीटों की संख्या 850: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 में प्रस्ताव है कि लोकसभा में अधिकतम 850 सीटें होंगी- 815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। फ़िलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं और संविधान में इनकी अधिकतम संख्या 550 तय की गई है। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का भी प्रस्ताव है, ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या पर लगी रोक को हटाया जा सके।

अनुच्छेद 81 के इन्हीं प्रावधानों की वजह से 1976 से ही लोकसभा की सीटों की संख्या में इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। तो अगर मौजूदा लोकसभा का आधार 1971 की जनगणना थी, तो लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किस आधार पर दिया जा रहा है?

इस सवाल का जवाब डीलिमिटेशन बिल (परिसीमन विधेयक 2026) में है, जिसे विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कहा गया है परिसीमन (डीलिमिटेशन) की प्रक्रिया 'ताज़ा प्रकाशित जनगणना' के आधार पर होगी। आख़िरी जनगणना 2011 में हुई थी। यानी इस विधेयक का आधार होगी 2011 में हुई जनगणना।

और यही वह बिंदु है जिस पर दक्षिणी राज्यों को अपने प्रतिनिधित्व में कमी होने की चिंता है। अब तक हर राज्य को मिलने वाली संसदीय सीटों की संख्या इस आधार पर तय होती रही है कि किसी राज्य की आबादी और उसकी निर्वाचन सीटों का अनुपात सभी राज्यों में लगभग बराबर रहे। यानी पूरे भारत में हर एक सीट लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी।

2. दक्षिण भारतीय राज्यों की आपत्तिः दशकों तक भारत में जनसंख्या वृद्धि असमान रही है, जिसमें दक्षिणी राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में आबादी के अनुपात में सीटें तय करने का यही मानदंड लागू किया गया, तो दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कमज़ोर हो जाएगा। ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें दक्षिणी राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी और संसद में इन राज्यों से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाने लगेगी। सरकार बार-बार यह आश्वासन देती रही है कि संसद की मौजूदा संरचना में राज्यों की आनुपातिक हिस्सेदारी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एक पोस्ट में कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विधेयकों में कुछ भी नहीं है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश 'लोकतंत्र पर हमला' है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष और बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वो दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर सीटें बढ़ाने के 'प्रो-रेटा मॉडल' का विरोध करें।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रस्तावित 850 सीटों के पुनर्गठन का सटीक ढांचा अभी साफ़ नहीं है। विधेयक में कहा गया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला परिसीमन आयोग अंतिम रूप देगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि भविष्य में किस जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा, यह संसद साधारण बहुमत से तय कर सकेगी. फिलहाल इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होती है- यानी संसद में दो-तिहाई बहुमत।

3. महिला आरक्षण-33%: महिला संगठनों और महिला सांसदों ने दशकों से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठाई है। फिलहाल लोकसभा में 78 महिला सांसद (कुल सीटों का 14%) और राज्यसभा में 42 महिला सांसद (कुल सीटों का 18%) है। 2023 में भारत ने एक कानून पारित किया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया, लेकिन इसे जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होना था। लेकिन नए संशोधन विधेयक में इसे 'ताज़ा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों' के आधार पर लागू करने की बात है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन हर डीलिमिटेशन साइकिल (परिसीमन चक्र) के बाद होगा। यह आरक्षण 15 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे संसद आगे बढ़ा सकती है।

हालांकि इस प्रावधान के इस अंतिम उद्देश्य पर ज़्यादातर पार्टियों में सहमति दिखती है लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे राज्य चुनावों के बीच लाने के समय पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद साकेत गोखले, ने लिखा, 'सरकार महिलाओं को बहाना बनाकर परिसीमन के अपने असली एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने सरकार महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक राहुल वर्मा ने कहा कि बीजेपी इस क़दम से राज्य चुनावों में फ़ायदा लेने की कोशिश कर सकती है। इस (बिल) से उन्हें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री ने घोषित किए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, बेटियां रहीं अव्वल

उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से रोशन हो रहा प्रदेश का भविष्य : मुख्यमंत्री

● कक्षा 12वीं में भोपाल की कु. खुशी राय और कु. चांदनी विश्वकर्मा ने किया संयुक्त रूप से टॉप ● कक्षा 10वीं में पन्ना जिले के गुनौर की कु. प्रतिभा सिंह सोलंकी रहीं टॉपर ● शासकीय स्कूलों का परिणाम निजी स्कूलों से रहा बेहतर ● अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिलेगा दूसरा अवसर

महापौर श्रीमती मालती राय ने खुशी राय के घर पहुंचकर बधाई दी।

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। बोर्ड परीक्षा के परिणाम ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। मध्यप्रदेश में दी जा रही उत्कृष्ट शिक्षा से हमारे विद्यार्थियों का भविष्य दिनों दिन रौशन हो रहा है। मुख्यमंत्री डा. यादव ने बुधवार को संवाद भवन (मुख्यमंत्री निवास) में माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा ली गई कक्षा 10वीं, 12वीं एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) मुख्य परीक्षा- 2026 के परिणाम घोषित किए।

वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 73.42 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 76.01 प्रतिशत रहा। शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम इस बार बीते 16 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ रहा है। पिछले वर्ष भी शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने ही बोर्ड परीक्षा में कीर्तिमान गढ़ा था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने शासकीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है, जिससे हमारे शासकीय स्कूल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूलों के परिणामों से आगे निकल रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फरवरी से मार्च के बीच कक्षा 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें 8 लाख 97 हजार विद्यार्थी शामिल हुए। हाईस्कूल परीक्षा में 73.42 प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 69.31 प्रतिशत छात्र और 77.52 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम 76.80 प्रतिशत और प्राइवेट स्कूलों का 68.84 प्रतिशत रहा है। दोनों में 8 प्रतिशत का अंतर है। यह सांदीपनि विद्यालयों के अनुकूल वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है। हाईस्कूल की मेरिट में 378 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है, जिसमें 235 छात्राएं और 143 छात्र हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी हमारी बेटियों ने ही बेटों से अधिक अंक हासिल किए हैं।

प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट में आगे निकले एमपी के सरकारी स्कूल, सीएम मोहन यादव ने ठोकी पीठ

सीएम मोहन यादव ने एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदेश का रिजल्ट अच्छा है। वहीं, प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के परिणाम अच्छे आए हैं। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस बार भी बेटियों ने अपना परचम लहराया है। साथ ही उन्होंने 10वीं की टॉपर प्रतिभा को बधाई दी है। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक लाए हैं। मोहन यादव ने कहा कि माता-पिता और बच्चे जान लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति-2020 लागू की। उसी का परिणाम है कि हम बच्चों का साल बचा लेते हैं। यह परीक्षा परिणाम स्वर्णिम मध्यप्रदेश की नई गाथा पेश कर रहा है।

संविदा कर्मचारियों की बड़ी जीत

● हाईकोर्ट ने कहा- बिना सुनवाई बर्खास्त करना मौलिक अधिकारों का हनन

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने या जेल जाने मात्र के आधार पर, बिना पक्ष सुने नौकरी से निकालना उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इसी आधार पर सीहोर जिले के एक रोजगार सहायक की बर्खास्तगी को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है।

जेल जाने और गैर-हाजिरी पर हटाना गलत- मामला सीहोर जिले के ग्राम कुंडियानातु का है, जहां गोपाल सिंह दिसंबर 2012 से संविदा रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ और वे 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहे।

● **30 दिन की शर्त और कानूनी खामी-** याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संबंधित आपराधिक मामले में न्यायालय उन्हें पहले ही दोषमुक्त कर चुका है। वहीं, अनुपस्थिति के मुद्दे पर प्रशासन ने धारा 18(6) का हवाला दिया था, जिसके तहत एक महीने की गैर-हाजिरी पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। जस्टिस विशाल धगट ने कहा किसी भी संविदा कर्मचारी को आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्त करना प्राकृतिक न्याय और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। प्रशासन को विधि अनुसार नई प्रक्रिया अपनानी होगी। हाईकोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि याचिकाकर्ता 30 अक्टूबर 2013 से अनुपस्थित था और बर्खास्तगी का आदेश महज 10 दिन बाद, 9 नवंबर 2013 को ही जारी कर दिया गया था।

शरद की सुबह

पलटकर देखने से

सांत्वना भर जाती है बोझिल दृश्य में
एक उदास आशा आशा से हो जाती है

इत्मीनान हो जाता है कि कोई
हाथ छुड़ाकर नहीं जा रहा है
पलटकर देखने से स्मृति में
पलटकर देखने की तस्वीर बन जाती है

पलटकर देखने से देख सकते हैं
कि पलटकर देखने से कोई
पत्थर का नहीं हो जाता

पलटकर देखने से याद आता है
हम सब मांसपेशियों से बने हैं
और यह हृदय भी आखिर
एक मांसपेशी है।

- कुमार अंबुज

ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर

शिक्षक सहित 3 की मौत,15 लोग घायल

राजगढ़ (नप्र)। राजगढ़ जिले में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एलएनटी मशीन ले जा रहे ट्रक की टक्कर में एक टीचर सहित 3 लोगों की मौत हो गई।वहीं, 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा 14 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे माचलपुर में पीपल्याकुल्मी रोड स्थित तेजरा पेट्रोल पंप के पास हुआ। ट्रॉली में सवार लोग एक विवाह समारोह में जा रहे थे।

झालावाड़ (राजस्थान) के अस्पताल चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया- राजगढ़ जिले के गांव सांवलपुरा से नयागांव जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगभग 35 से 40 लोग सवार थे। वे एक शादी समारोह में खाना खाने जा रहे थे।

गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली अनियंत्रित होकर पास के नाले में पलट गई।

● **एक महिला की मौके पर ही मौत, दो ने रास्ते में तोड़ा दम-** हादसे में कचनारिया (राजगढ़) निवासी कबूबाई (60) की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक बालकृष्ण दांगी (45) और सलोनी (10) ने अस्पताल ले जाते समय झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल माचलपुर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजगढ़ जिला अस्पताल और झालावाड़ रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज माचलपुर अस्पताल में जारी है।

बेहद खतरनाक होंगे 6वीं जनरेशन के फाइटर जेट

● डबल स्ट्रेटेजी से आकाश में अब और भी घातक होगा भारत

भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए दोहरी रणनीति पर काम जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना भविष्य की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। वायुसेना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भागीदारी पर विचार कर रहा है, तो दूसरी ओर पूर्ण रूप से स्वदेशी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने काम किया जा रहा है। 2026 की शुरुआत में ही बेंगलुरु में आयोजित छठे भारत-फ्रांस वार्षिक डिफेंस डायलॉग समिट के दौरान भारत ने यूरोपीय फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में शामिल होने की रुचि दिखाई थी। इसके अलावा भारत के पास यूके-इटली-जापान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम भी एक प्रमुख विकल्प बना हुआ है।

यूरोपियन कंसोर्टियम में शामिल होने पर विचार कर रहा भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत किसी एक यूरोपीय कंसोर्टियम (जीएसीएस या एफसीएएस) में शामिल होने की बातचीत कर रहा है। लेकिन साथ ही खुद का छठे जनरेशन के फाइटर जेट को विकसित करने के विकल्प भी रखा है। यह प्लेटफॉर्म भारत की खास जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और दोनों से अलग हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता हासिल करना बहुत जरूरी है। स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मार्च 2026 में संसदीय स्थायी समिति को दी गई रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि भारतीय वायुसेना दोनों में तुरंत शामिल होने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य के बेहतरीन विमानों की दौड़ में भारत पीछे न रह जाए।

जीसीएपी और एफसीएएस का ब्लूप्रिंट तैयार

जीसीएपी और एफसीएएस के मौजूदा ब्लूप्रिंट से पता चलता है कि ये अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय लड़ाकू विमान भारत के आगामी पांचवीं पीढ़ी की परियोजना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तुलना में कहीं अधिक भारी होंगे। हाल में एलसीए के प्रोटोटाइप विकास के लिए सरकार से 15,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम मंजूरी मिली है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि दोनों का अधिकतम वजन टेक-ऑफ के समय 30 से 35 टन के बीच हो सकता है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी

● शपथ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के छुए पैर ● जेडीयू से विजय चौधरी-बिजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम

पटना (एजेंसी)। सम्राट चौधरी बिहार 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतिश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री के पिता शकुनी चौधरी ने कहा, कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमने कई पार्टियों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतिश की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गया। मेहनत रंग लाती है जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा।'

बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतिश मॉडल ही चलने वाला है

शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बाद करते हुए सम्राट चौधरी ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के विकास और शासन व्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी और नीतिश मॉडल ही चलेगा। पीएम मोदी ने भी सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा-बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं! उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता-जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

कोर्ट धार्मिक मान्यताओं पर फैसला नहीं दे सकता

● सबरीमाला मंदिर प्रशासन बोला-कुछ लोगों का अधिकार पूरे समुदाय के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के वकील एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, किसी धर्म की प्रथा सही है या नहीं, यह तय होगा उसी समुदाय की आस्था के आधार पर। जज खुद यह तय नहीं करेंगे कि धर्म के लिए क्या सही है, क्या गलत। उन्होंने कहा कि धर्म एक समूह या समुदाय

की आस्था से जुड़ा है। इसलिए कुछ लोगों (महिलाओं की एंट्री) के अधिकार को पूरे समुदाय के अधिकारों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। इससे पहले 7 से 9 अप्रैल तक 3 दिन सुनवाई के दौरान भी महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखी गईं। केंद्र सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए बैन हटा दिया। इसके बाद दायर पुनर्विचार याचिकाओं के आधार पर 7 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न तय किए गए हैं, जिन पर अब बहस हो रही है।

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले

रानी लक्ष्मीबाई की तरह राजमाता सिंधिया ने हिलाई थी सत्ता

बस्तर के राजा की हत्या के विरोध में गिराई थी कांग्रेस की सरकार

भोपाल (नप्र)। राजधानी के रवींद्र भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित 'नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा' सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नारी शक्ति के ऐतिहासिक और राजनीतिक पराक्रम को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर अंचल की राजमाता विजयाराजे सिंधिया के योगदान का स्मरण करते हुए उनकी तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झांसी की रानी ने तलवार उठाकर अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी थी, ठीक उसी प्रकार राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस शासन के दौरान हुए अन्याय और बस्तर के राजा के साथ हुए अपराध के विरोध में राजसी सुखों का त्याग कर जनबल के माध्यम से सत्ता को हिला दिया था।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजमाता ने कभी पद का मोह नहीं किया और केवल जनता की लड़ाई लड़ती रहीं।

संवैधानिक शक्ति और मोदी का संकल्प-मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि असंभव कार्यों को संभव बनाना मोदी जी की पहचान है। उन्होंने शाहबानो प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि 40 साल पहले जो गलती लोकसभा में हुई थी, उसे सुधारकर मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के दंश से मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक काम वर्तमान सरकार ने किया है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 16 अप्रैल 2026 की तारीख महिला सशक्तिकरण के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी, जब देश होली और दिवाली एक साथ मनाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनोनयन को देश के सर्वोच्च पद पर मातृशक्ति के गौरव का प्रतीक बताया।

कृष्णा गौर बोलीं- लोकसभा में मात्र 14 प्रतिशत और विधानसभा में 11 फीसदी महिलाएं-सम्मेलन में मंत्री कृष्णा गौर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्र निर्माण की धुरी बताया। उन्होंने वर्तमान राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि वर्तमान में लोकसभा में मात्र 14 प्रतिशत और मध्य प्रदेश विधानसभा में केवल 11 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह कानून इस बड़े अंतर को पाटने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। श्रीमती गौर ने जोर देकर कहा कि अब महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि देश के भविष्य की सारथी बनेंगी। यह कानून नारी को शक्ति स्वरूपा और अर्द्धनारीश्वर के रूप में स्थापित करने का संवैधानिक संकल्प है।

निर्मला भूरिया बोलीं: 12 हजार मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण आंगनवाड़ियों में बदला-महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि प्रदेश की 12 हजार मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण आंगनवाड़ियों में तब्दील कर दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता और सहायिकाओं के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हाईस्कूल की टॉपर छात्रा खुशी रायवाडे और चांदनी विश्वकर्मा को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सम्मेलन में ये महिला जनप्रतिनिधि रहीं मौजूद

इस सम्मेलन में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मंत्री निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, संपतिया उईके, महापौर मालती राय, विधायक अर्चना चिटनीस, सागर सांसद लता वानखेड़े, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे और शिक्षाविद् शोभा पैठणकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में महिला आरक्षण को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देने का आह्वान किया।

अमित शाह के साथ इस मुलाकात के क्या अर्थ, राहत या इंकार

भोपाल। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक बीते कुछ दिनों से संकटों से घिरे हुए हैं। जबलपुर (सिहोरा) में उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक अवैध उत्खनन की शिकायत हुई। मामले की जांच के बाद खनिज विभाग ने लगभग 443 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जज को फोन करने के आरोपों के बाद, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि भाजपा विधायक संजय पाठक पर कटनी अवैध खनन से जुड़े मामले में सुनवाई कर रहे जज को प्रभावित करने के लिए फोन करने का आरोप है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने सितंबर 2025 में इस घटना का खुलासा करते हुए खुद को केस से अलग कर लिया था, जिसके बाद यह मामला चीफ जस्टिस के पास गया। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्यायिक निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत में विधायक संजय पाठक की तरफसे दलील दी गई कि कॉल लगना गलती है। उन्होंने हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगी है। अदालत ने माफी स्वीकार नहीं की है। विधायक संजय पाठक को 21 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

इन परिस्थितियों में भाजपा विधायक संजय पाठक ने राहत पाने के लिए हर स्तर पर प्रयत्न किए हैं। उनकी मुराद बीते सप्ताह पूरी हुई जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मिल गया। मुलाकात हुई भी व सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल भी हुई। इस तस्वीर में हावभाव देख कर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा विधायक संजय पाठक को राहत का आश्वासन मिला या संकट बरकरार है।

राजेंद्र भारती की इस पीड़ा का उपचार कहां है

दतिया की विधानसभा सीट खाली होना केवल एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि राजनीतिक घमासान बन गया है। दतिया से जीत कर भी कोर्ट में हार गए कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने अपनी सजा को एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। भारती ने कहा कि उन्हें झुकने और बिकने के लिए 70 करोड़ रुपए तक का प्रलोभन दिया गया था, जिसे ठुकराने पर उन्हें निपटाने की धमकी दी गई थी। मई 2024 में दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का संदेश देते हुए कहा कि आप सारे केस वापस ले लीजिए, भाजपा में आ जाइए और आपको किसी निगम-मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दल न बदल कर आज वे हारे हुए हैं। मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। वहां तो सुनवाई होगी ही लेकिन राजेंद्र भारती अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। वे कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी असली पीड़ा 'विश्वासघात' की है। विश्वासघात जो व्यवस्था के स्तर पर उनके साथ हेने का वे दावा कर रहे हैं। विश्वासघात जो उन्होंने प्रलोभन में आ कर नहीं किया। दल न बदलने की कीमत उन्हें विधायकी खोकर चुकानी पड़ी। उनकी पीड़ा का इलाज तो जनता के पास ही है। यदि उपचुनाव होता है तो जनता के पास राजेंद्र भारती की पीड़ा पर अपना निर्णय देने का अवसर होगा। इस

क्या विफल हो गया भाजपा का राज्यसभा गणित?

मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी राज्यसभा की खाली सीटों का जिक्र होता है, तो विधायकों में तोड़फोड़ सबसे पहले सुर्खियों में आती है। मई 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भी यही माहौल था। चर्चाएं आम थीं कि भाजपा अपनी भारी बहुमत और 'क्रास वोटिंग' रणनीतियों के दम पर कांग्रेस के खाते वाली तीसरी सीट भी अपनी झोली में डालने की तैयारी में है। अब मिल रहे संकेत बताते हैं कि भाजपा के इस फार्मूले की हवा निकल गई है। भाजपा तीसरी सीट के लिए फिलहाल हाथा-पैर नहीं मार रही है। इस संबंध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का यह बयान चर्चा में रहा कि असल में भाजपा फेल हो गई। वह कांग्रेस में तोड़फोड़ नहीं कर पा रही है इसलिए चुप बैठ गई है। पीसी शर्मा के मुताबिक, भाजपा ने पूरी कोशिश की थी कि वे कुछ कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में कर लें, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो चुप्पी साध ली। यह चुप्पी दरअसल एक रणनीतिक हार की तरह देखी जा रही है। खासकर तब जब दतिया सीट को तुरंत ही खाली घोषित की गई व बीना विधायक निर्मला सप्रे की योग्यता पर डेढ़ साल में कोई फैसला नहीं किया गया है। भाजपा में शामिल हो चुकी विधायक निर्मला सप्रे स्वयं को कांग्रेस में ही बता रही है। संभव है कि मई में होने वाले राज्यसभा के चुनाव तीन नहीं बल्कि चार सीटों पर हों क्योंकि मध्य प्रदेश से राज्य सभा सदस्य केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वे जीत जाएंगे प्रदेश की चौथी सीट खाली होगी। फिलहाल, मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों का यह खेल अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां भाजपा अपनी दो सुरक्षित सीटों पर संतोष करती दिख रही है और कांग्रेस अपनी इकलौती सीट को बचा ले जाने के आत्मविश्वास से लबरेज है। तीसरी सीट पर मुकाबले से ज्यादा अब भाजपा में दो सीटों पर दावेदारी कर रहे नेताओं में से उपयुक्त का चयन करना बड़ी चुनौती है।

अनुवाद कौशल कार्यशाला में डॉ. जवाहर कर्नावट का व्याख्यान

भोपाल। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की शिक्षाशास्त्री चतुर्थ सत्रार्द्ध की शैक्षणिक गतिविधि अन्तर्गत अनुवाद कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. जवाहर कर्नावट, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल का सारगर्भित व्याख्यान हुआ उन्होंने अनुवाद के विभिन्न प्रकार बताते हुए अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो श्रीगोविन्द पाण्डेय ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए एवं अनुवाद से संबंधित अलग अलग राज्यों की भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संयोजन डा. राकेश कुमार वर्मा एवं डॉ. एस कृष्णा ने किया । परिसर निदेशक प्रो. हंसधर झा ने डॉ. कर्नावट का शाल एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। इसी अवसर पर पूर्व में आयोजित योगाभ्यास गतिविधि के उपलक्ष में विद्यार्थियों द्वारा योगासन का प्रदर्शन भी किया गया जिसका प्रशिक्षण डॉ. प्रवेश जाटव द्वारा दिया गया, कार्यक्रम का संचालन छात्र चंद्रमणि ने किया। कार्यक्रम में प्रो. के. हर्षकुमार, प्रो. सुबोध शर्मा, प्रो भारत भूषण मिश्र,प्रो अशोक कुमार कच्छवाह सहित बड़ी संख्या में छात्र- छात्राएं एवं प्राध्यापक गण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसे में | अब तक 17 की मौत

36 लोग झुलसे, वेदांता मृतकों के परिजन को 35-35 लाख मुआवजा और नौकरी देगी

सक्ती (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 17 मौतें हो चुकी हैं। 4 की मौके पर ही जान गई, जबकि 6 की मौत रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, 5 की जिला अस्पताल रायगढ़ और 2 की रायपुर के कालड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर ब्लास्ट हो गया था। मृतकों में 4 छत्तीसगढ़ से हैं, जबकि बाकी 13 यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हैं। हादसे में कुल 36 लोग झुलसे हैं, 18 घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। हादसे के बाद प्लांट के बाहर मजदूरों के परिजन ने हंगामा

किया। उन्होंने प्रबंधन पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। कुछ मजदूर लापता हैं। परिजन का कहना है कि प्रबंधन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वेदांता प्रबंधन ने मृतक परिजन को 35-35 लाख रुपए सहायता राशि और नौकरी देने का ऐलान किया है। घायलों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में 10 भर्ती

प्लांट हादसे में घायल 10 लोगों का इलाज रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में चल रहा है। सभी 15 से लेकर 95-100 फीसदी तक झुलसे हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें मनीष गिरी, कार्तिक महतो, बृजेश कुमार, केशव चंद्रा, भुवनेश्वर चंद्रा, अभिषेक चंद्रा, नदीम अंसारी, मिलन वारे, संदीप और शिवनाथ मुर्मू शामिल हैं। इसके अलावा, बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल रायगढ़ में बनवारी लाल, उपेंद्र और परदेशी लाल चंद्रा का इलाज जारी है। वहीं दो मजदूरों उमेंद्र और किस्मत अली का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है।

पाकिस्तान की भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश

जम्मू-कश्मीर में आतंक के लिए ला रहा अफगान युद्ध के ट्रेंड सैनिक

श्रीनगर (एजेंसी)। फरवरी में, भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक पाकिस्तानी नागरिक आदिल को मार गिराया। इसमें जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली थी, वह सिर्फ उसकी ऑपरेशनल मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उसका बैकग्राउंड भी था। एक रिपोर्ट में आदिल को अफगानिस्तान युद्ध का एक अनुभवी लड़ाका बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आदिल ने 2021 तक तालिबान के साथ

मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद उसे भारत की तरफ भेज दिया गया था। लगभग 18 महीनों तक, वह पकड़े जाने से बचता रहा। इस दौरान वह छतरू सेक्टर की प्राकृतिक गुफाओं और ऊंची जगहों पर बने ठिकानों से अपनी गतिविधियां चलाता था। इन्हीं जगहों से उसने कई हमलों की साजिश रची और भारतीय सैनिकों के शवों को क्षत-विक्षत करने जैसे बेहद क्रूर कृत्यों में शामिल रहा।

कई बार चलाए गए घेराबंदी और तलाशी अभियानों के बावजूद वह बच निकला। बताया जाता है कि वह लगभग बीस बार बच निकला था। यह उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग और युद्ध के मैदान के माहौल में ढल जाने की क्षमता को दर्शाता है। माना जा रहा है कि उसे रूस्त की ओर से युद्ध-नीतियां सिखाई गईं ऑपरेशन त्राशी के सफल संचालन के बाद किश्तवाड़ का दौरा किया।

अनुभव का इस्तेमाल, छद्म युद्ध को जारी रखना

कश्मीर में अफगानिस्तान की जंग के माहिर लड़ाकों की मौजूदगी से पता चलता है कि पाकिस्तान की छद्म युद्ध की रणनीति में बदलाव आ रहा है। अफगानिस्तान में मिशन खत्म होने के बाद, प्रशिक्षित आतंकवादियों का एक बड़ा समूह उपलब्ध हो गया है। उन्हें भारत की तरफ मोड़कर, इस्लामाबाद बिना सीधे सैन्य टकराव के भारत पर दबाव बनाए रख सकता है।

पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर 'सुप्रीम' रोक

कांग्रेस नेता को तगड़ा झटका, कहा-हम आश्चर्यचकित हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को बहुत बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कांग्रेस नेता को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली न केवल ट्रांजिट अग्रिम जमानत को स्टे कर दिया है, बल्कि उन्हें दी गई राहत पर

आश्चर्य भी जताया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल शरतचंद्र चांदूरकर की बेंच ने बुधवार को इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोटिस जारी किया है। पवन खेड़ा को इसका जवाब तीन हफ्तों के अंदर देना है।

गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दे सकते हैं पवन खेड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पवन खेड़ा इस दौरान असम के क्षेत्राधिकार वाली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका देते हैं तो सर्वोच्च अदालत द्वारा पास अंतरिम आदेश का उस याचिका पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इस केस में असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पवन खेड़ा की याचिका में यह नहीं बताया गया था कि तेलंगाना उनके मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है। तुषार मेहता ने दलील दी कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी के खिलाफ एक बड़ा अपराध है।

सभी संभागों में गेहूँ का उपार्जन शुरू : खाद्य मंत्री

42689 किसानों से 18 लाख 97 हजार 480 क्विंटल गेहूँ उपार्जित

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 42 हज़ार 689 किसानों से 18 लाख 97 हजार 480 क्विंटल गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 28 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा चुका है। गेहूँ का उपार्जन सभी संभागों में शुरू हो चुका है। अभी तक 2 लाख 58 हजार 644 किसानों द्वारा 1 करोड़ 13 लाख 95 हजार 407 क्विंटल गेहूँ के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। किसान गेहूँ बिक्रय के लिये 24 अप्रैल 2026 तक स्लॉट बुक कर सकते हैं। खरीदी के लिये 3171 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। गेहूँ की खरीदी कार्यालयीन दिवसों में होती है।

उपार्जन केंद्र में किसानों के लिये गेहूँ बिक्री की सभी सुविधाएं– मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि जिन जिलों में गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहाँ गेहूँ विक्रय की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उपार्जन केन्द्रों में छायादार स्थान में

बैठने और पेय जल की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र में बारदाने, तौल कांटे सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और उपज की साफ सफाई के लिए पंखा, छनना आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ को रखने के लिये जूट बारदानों के साथ ही पीपी/एचडीपी बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उपार्जित गेहूं में से 8 लाख 65 हजार 600 क्विंटल गेहूँ का परिवहन किया जा चुका है।

प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकार्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष युद्ध की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से एक लाख मीट्रिक टन अधिक है।

दोस्त को लाठी-डंडों से पीटा, छात्रा से किया रेप

महू के लगनचा मंदिर में दर्शन करने गई युवती, दो पर केस दर्ज

महू (नप्र)। महू के बदगोंदा थाना क्षेत्र स्थित बेरछा जंगल में एक छात्रा से दो बदमाशों ने रेप किया। आरोपियों ने उसके साथ आए दोस्त को लाठी-डंडों से पीटकर उसे जंगल से भगा दिया। घटना मंगलवार शाम की है। दरअसल, इंदौर के एक कॉलेज की छात्रा मंगलवार दोपहर अपने दोस्त के साथ बेरछा क्षेत्र के जंगल में पहुंची थी। दोनों लगनचा मंदिर में दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद वे जंगल में एक सुनसान जगह पर बैठे। इसी दौरान पीछे से दो बदमाश आए।

दोस्त को लाठियों से मारकर भगाया, छात्रा से किया रेप– पुलिस के अनुसार, दोनों युवकों ने युवती के दोस्त को लाठी से पीटकर वहां से भगा दिया और छात्रा के साथ रेप किया। पीड़िता के दोस्त ने जंगल से बाहर आते ही डायल-112 पर कॉल किया। सूचना मिलने पर बड़गोंदा पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक और छात्रा को थाने ले आई। घटना के बाद युवक-युवती का मेडिकल टेस्ट कराया गया।

आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, युवक की गर्दन और हाथों में चोट के निशान पाए गए हैं। छात्रा की गर्दन और चेहरे पर भी खरोंचें मिली हैं। बताया गया है कि छात्रा ने बदमाशों से बचने के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण उसके चेहरे और गर्दन पर नाखूनों से चोटें आईं। इस मामले में इंदौर ग्रामीण के एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि देर रात बड़गोंदा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और उनकी तलाश जारी है।

तप रहा एमपी... तापमान 42 डिग्री के पार

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर-जबलपुर भी गर्म; 16 अप्रैल से लू चलेगी, 17 जिलों में अलर्ट

भोपाल (नप्र)। तेज गर्मी से पूरा मध्य प्रदेश तप गया है। दिन का तापमान 42 डिग्री और रात 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी गर्मी का असर बढ़ा है। मंगलवार को नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रतलाम, खजुराहो समेत 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री या इससे अधिक रहा।

मौसम विभाग भोपाल ने 16 मार्च से प्रदेश में हीट वेव यानी, लू चलने का अलर्ट जारी किया है। 16, 17 और 18 अप्रैल को प्रदेश के 17 जिले लू से प्रभावित रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को पूरे प्रदेश में तेज गर्मी रही। मौसम विभाग की माने तो नर्मदापुरम में दिन के साथ रात भी सबसे गर्म है। रात में तापमान 25 डिग्री रहा। इसी तरह रतलाम में 41.4 डिग्री, खजुराहो-नौगांव में 41 डिग्री, धार में 40.6 डिग्री, बैतूल में 40.5 डिग्री, श्योपुर-रायसेन में 40.4 डिग्री, शाजापुर, गुना-खरगोन में 40.2 डिग्री, छिंदवाड़ा में 40.1 डिग्री, दमोह, सागर-मलाजखंड में तापमान 40 डिग्री रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में भोपाल-जबलपुर में सबसे ज्यादा 39.6 डिग्री, इंदौर में 39.8 डिग्री और ग्वालियर-उज्जैन में 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

नया सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन असर नहीं– मौसम विभाग के अनुसार, 15 अप्रैल को नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, लेकिन यह कमजोर रहेगा। इसका असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ही दिखाई देगा। यानी, अब प्रदेश में तेज गर्मी वाला दौर ही रहेगा। गर्मी बढ़ने से लोग उससे बचने के तरीके भी तलाश रहे हैं। कोई मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकल रहा है तो कोई गन्ने का ज्यूस, कोल्ड्रिंक्स, आइस्क्रीम का लुत्फ उठा रहा है। गर्मी का असर बढ़ते ही मौसम विभाग ने बचाव की एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वे दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में न रहे। हल्के वजन और रंग के सूती कपड़े पहनें। बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर ध्यान रखें।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा जिले में

लोक निर्माण विभाग के आधारभूत संरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की

कमिश्नर बंगला से ढेकहा तिराहे तक 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा फ्लाइओवर

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में रीवा जिले में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क एवं आधारभूत संरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अंतिम रूप देकर टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाए जिससे विकास कार्य समयबद्ध रूप से शुरू हो सकें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा में कमिश्नर बंगला से ढेकहा तिराहे तक 700 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित फ्लाइओवर निर्माण कार्य पर विशेष चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह फ्लाइओवर वर्तमान यातायात दबाव को कम करने के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं दूरदर्शी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करेगा। इसके निर्माण से शहर में सुगम एवं व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित होगा तथा यातायात बाधाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने लक्ष्मण बाग से कुठुलिया मार्ग में बिछिया नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कुठुलिया मार्ग का विकास लक्ष्मण बाग सहित संस्कृत विश्वविद्यालय तक सहज एवं सुगम पहुंच का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों को आवागमन में विशेष सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण कार्य को भी परियोजना में शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति एवं कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की।

चिकित्सा छात्रों को समय से योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान करें सुनिश्चित : उप मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा छात्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभों के भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर्विभागीय समन्वय से छात्रवृत्ति एवं संबंधित हितलाभों का समयबद्ध एवं सुचारू भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता

है कि छात्रों को उनकी पात्रता अनुसार मिलने वाले सभी लाभ बिना किसी विलंब के प्राप्त हों। उन्होंने निर्देशित किया कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो तथा यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित निराकरण किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही संबल योजना एवं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ अरुणा कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

छिंदवाड़ा में बोर्ड रिजल्ट देखकर छात्रा ने दी जान

प्रशासन ने कहा- परिणाम देखकर गलत कदम नहीं उठाएं

छिंदवाड़ा (नप्र)। बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शहर के मोहन नगर क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा सानिया ने तनाव के चलते जान दे दी है। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई, वहीं पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

रिजल्ट आने के बाद तनाव में आ गई

जानकारी के मुताबिक, सानिया परासिया क्षेत्र की रहने वाली थी और पिछले कुछ समय से छिंदवाड़ा में अपने नाना-नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। सोमवार को जैसे ही बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, वह काफी तनाव में आ गई। परिजनों का कहना है कि वह रिजल्ट को लेकर चिंतित थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल– घटना के बाद परिवार पूरी तरह सदमे में है। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की भीड़ घर के बाहर जुट गई। हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध है और यही सवाल कर रहा है कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस– घटना की जानकारी मिलते ही छिंदवाड़ा स्थित कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

गोपाल सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा परीक्षा परिणाम को लेकर कोई भी गलत कदम न उठाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की ओर से इम्प्रूवमेंट परीक्षा का विकल्प दिया जाता है, जिससे छात्र अपने अंक सुधार सकते हैं।

बढ़ता परीक्षा तनाव बना चिंता का विषय

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि परीक्षा और परिणाम को लेकर बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि वे अपनी परेशानियां खुलकर साझा कर सकें।

वर्ल्ड आर्ट दिवस पर

संस्कृति विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव श्री तिवारी को दिव्यांग पूजा ने चित्रकला भेंट की

भोपाल (नप्र)। वर्ल्ड ऑर्ट दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग होनहार आर्टिस्ट पूजा प्रजापति जी ने सीएम के सांस्कतिक सलाहकार राम तिवारी को एक सुंदर एवं भावपूर्ण पेंटिंग भेंट की गई। इच्छाशक्ति हो तो हर कार्य संभव है यह पूजा की चित्रकारी में दिखता है। पूजा प्रजापति जी दिव्यांग होते हुए भी अपनी कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर भोपाल में रहकर अपना जीवन-यापन एवं भरण-पोषण कर रही हैं तब लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के श्रेष्ठ समृद्ध भारत की कल्पना कहीं ना कहीं साकार हो रही है जिसमें शारीरिक विषमता (दिव्यांग) होने के बाद भी गर्व से अपनी कला का प्रदर्शन कर नारी शक्ति के सशक्तिकरण को सार्थक कर रही है। यह उनकी चित्रकला में परिलक्षित होता है। पूजा का आत्मविश्वास और सृजनशीलता और सफलता यह दर्शाती है कि, कोई भी विषमता कभी आड़े नहीं आती है अगर आपकी इच्छाशक्ति और संकल्पशक्ति अपने कार्य को अनवरत करने की हो तो। संस्कृति विभाग के पूर्व सचिव रामजी तिवारी ने दिव्यांग पूजा की कलाकृति कि न केवल सराहना की बल्कि विषमताओं के बावजूद उनकी की तारीफ की।यह भेंट केवल एक चित्र नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, संघर्ष और सम्मान का एक प्रेरणादायक संगम है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी चिंतक अनिल बुलचंदानी बापू एवं नवीन मालवीय भी उपस्थित थे।

आशा भोंसले के नाम पर मप्र सरकार शुरू करेगी राष्ट्रीय सम्मान

सुर सम्राज्ञी को मोहन यादव सरकार की बड़ी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। भारतीय संगीत के स्वर्णिम युग की एक और महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। रविवार, 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में सुर सम्राज्ञी आशा भोंसले का निधन हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस महान हस्ती की विरासत को संजोने और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर एक विशेष 'राष्ट्रीय पुरस्कार' शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

लता मंगेशकर के बाद अब आशा भोंसले के नाम पर सम्मान– मध्य प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ इस प्रस्ताव पर अंतिम चर्चा के बाद पुरस्कार की रूपरेखा तय की जाएगी। मंत्री लोधी के अनुसार, राज्य में पहले से ही लता मंगेशकर के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रदान किया जाता है। अब उनकी छोटी बहन और संगीत जगत की दिग्गज आशा भोंसले के नाम पर पुरस्कार स्थापित करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

प्रस्तावित आशा भोंसले एक्सीलेंस अवॉर्ड का उद्देश्य न केवल स्थापित कलाकारों को सम्मानित करना होगा, बल्कि इसके जरिए उभरते हुए गायकों को नकद पुरस्कार, प्रदर्शन के अवसर और मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य की सांस्कृतिक विरासत और संगीत प्रतिभाओं को वैश्विक मंच दिया जा रहा है।

आठ दशकों का सफर और 12,000 गीतों का जादू– आशा भोंसले का संगीत सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। 1943 में मात्र 10 साल की उम्र से गायकी शुरू करने वाली आशा ताई ने आठ दशकों के करियर में कई भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उनकी बहुमुखी आवाज ने फिल्मी गीतों से लेकर गजल, भजन और पॉप संगीत तक, हर विधा को जीवंत किया। साल 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र सिंह लोधी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश ने कहा आशा भोंसले केवल एक गायिका नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की एक जीवंत संस्था थीं। उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करना मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान न केवल उनकी यादों को संजोएगा, बल्कि संगीत की दुनिया में नए सितारों को चमकने का मौका देगा। अधिकारियों का मानना है कि यह पुरस्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। जिस तरह आशा ताई ने अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई, यह पुरस्कार भी संगीत की नई पौध को उसी ऊंचाई तक पहुंचने का हौसला देगा। हालांकि पुरस्कार की शुरुआत की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इस पहल ने देशभर के संगीत प्रेमियों के बीच एक सकारात्मक लहर पैदा कर दी है।

संपादकीय

नीतीश युग खत्म: सम्राट युग शुरू

बिहार में बहुप्रतीक्षित भाजपा के सम्राट युग की शुरूआत हो चुकी है। राज्य के 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली में राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपनी बची खुची राजनीति करेंगे, जबकि बिहार की कमान अब अति पिछड़ी कोइरी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी के हाथ आ गई है। सम्राट को सोमवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ तय फार्मूले के मुताबिक जेडीयू के दो विधायकों विजय चौधरी और विजेन्द्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी पहले राजद में रह चुके हैं। वो खांटी आरएसएस के नहीं है। फिर भी उनका चुनाव नीतीश की सहमति से किया गया है, क्योंकि वो अति पिछड़ी कोइरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार को नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। क्योंकि इसमें एनडीए के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना होगा। इसको लेकर दलों में आपसी खींचतान भी दिखाई दे सकती है। बहरहाल सम्राट के रूप भें भाजपा ने बिहार में ईबीसी का दांव खेला है, पार्टी को उम्मीद है कि इसका लाभ भाजपा को पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, जहां कोईरी कुशवाह जाति के लोग काफी संख्या में हैं। पद संभालते ही सम्राट चौधरी ने भी कहा कि वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यह शुरूआती गलबहियां हैं। अब बिहार की सरकार दिल्ली के इशारे पर चलेगी। क्योंकि सम्राट दिल्ली की भी पसंद है।सम्राट चौधरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो कभी नीतीश को कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे। शकुनि चौधरी खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। उनके बेटे सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। जबकि शकुनी चौधरी ने साल 1999 में बिहार में राबड़ी देवी की सरकार का साथ दिया था, हालाँकि वो खुद उस वक्त सांसद थे। 2000 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2014 में तत्कालीन जीतनराम मांझी सरकार में वो नगर विकास विभाग के मंत्री बनाए गए थे। मई 2014 में सम्राट चौधरी ने आरजेडी से इस्तीफ़ा दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। साल 2015 में बिहार में पहली बार महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उस वक्त जेडीयू के रामानंद प्रसाद सिंह को परबत्ता सीट से टिकट दिया था और वो जीत गए थे।

साल 2017 में सम्राट चौधरी ने जेडीयू से भी इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2024 की शुरुआत में नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होकर फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री बनाए गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन की जीत के बाद फिर से सम्राट चौधरी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट के सामने बिहार को आगे ले जाने की बड़ी चुनौतियां हैं। क्योंकि विकास के सूचकांक भी बिहार अब भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। विकास के साथ सुशासन और रोजगार भी प्रमुख मुद्दा है, जिस पर सम्राट चौधरी को रिजल्ट देना होगा। उधर नीतीश के जाने के बाद उनकी पार्टी जदयू का भविष्य अब अधर में है। आश्चर्य नहीं कि पार्टी भाजपा में विलीन हो जाए।

जनगणना में जरूरी प्रवासी मजदूर

नजरिया

अरविन्द मोहन

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इस बार के चुनाव में भी मजदूरों के पलायन का सवाल आ ही गया। कैसा भी चुनाव हो, विकसित राज्य का हो या पिछड़े राज्य का, पलायन और प्रवासी मजदूर मुद्दा बन ही जाते हैं। पिछड़ा बिहार हो या विकसित पंजाब, यह मुद्दा है। दिल्ली में तो प्रवासियों का वोट निर्णायक ही माना जाने लगा है। इस बार चुनाव न बिहार में है, न पंजाब में और न दिल्ली में। केरल में चुनाव है तो वह भी खाली होने लगा है। प्रवासी मजदूर सिर्फ रसोई गैस की तंगी से ही नहीं, वोट देने के लिए भी अपने देस बंगाल और असम लौट रहे हैं। तमिलनाडु में बहुत बिहारी मजदूर हैं तो उनका लौटना खास चर्चा में नहीं है क्योंकि अभी वे वहां के वोटर नहीं हैं।

केरल में आर्थिक जीवन ही नहीं, हर तरफ प्रवासी बिहारी, झारखंडी, बंगाली और असमिया या ओडिया मजदूरों का 'राज' है। उनके हिसाब से सस्ते होटलों का खाना बनता है, सिनेमा दिखाया जाता है, बसों पर हिन्दी और बांग्ला में तख्तियां लगाकर उनके आने-जाने के स्थान की सूचना दी जाती है, कमरों का किराया तय होता है। उनके बंगाल और असल लौटने की वजह मतदाता सूचियों का बृहद संशोधन और उस नाम पर लोगों के नाम काटने-जोड़ने का खेल भी एक वजह है। कई तो अपने अपूर्ण या विवादित दस्तावेज की गवाही के लिए पहले आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर को लगता है कि वोट गिराने से उनकी नागरिकता पुख्ता होगी। इस बार प्रवासी मतदाताओं की उस तरह लल्लो-चप्पो नहीं हो रही है जैसा अक्सर बिहार, दिल्ली या फिर पंजाब चुनाव में दिखाई देता है।

अब तो मुंबई और सूरत वगैरह में भी चुनाव के समय प्रवासियों की आवाजाही और वोट का सवाल प्रमुख बनता है। पार्टियां खास तौर से उन राज्यों के नेताओं को जिम्मा सौंपती हैं। मोटा फंड़ भी दिया जाने लगा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोग भी पेड़-लीव और रिटर्न प्लेन टिकट के साथ भेजे जाते हैं। मजदूरों को साड़ी-बिंदी समेत छुट्टी के साथ घर भेजा जाता है। पिछले बिहार चुनाव में दिल्ली और हरियाणा से स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं और मजदूरों को मुफ़्त लाया, ले जाया गया। भाजपा ने यह काम किया तो विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने का मौका मिला। इस बार न पक्ष सक्रिय है, न विपक्ष। सारा जतन प्रवासियों को खुद करना है। हां, इतना जरूर हुआ है कि बार-बार दिखने वाली दुर्दशा के चलते इस बार मीडिया, खासकर सोशल मीडिया में मजदूरों की घर-वापसी एक मुद्दा बनकर सामने आई है। इसमें मुख्य मसला रसोई गैस के संकट का है, पर किसी बहाने अगर समाज को इनकी सुध आने लगी है तो यह शुभ लक्षण है।

बीते वर्षों से इन अभागे मजदूरों के हिस्से जो ज़लालत और परेशानी की जिंदगी रही है, उसमें ऐसे मौके-कुमौके की चर्चा से ज्यादा बदलाव नहीं आना है। उससे न तो अमीर और गरीब इलाकों के विकास का क्रम उलटेगा और न इस फासले से पैदा होने वाले पलायन के हालात। हमारा विकास ऐसे ही आड़ा-तिरछा बढ़ता रहा है और उसी क्रम में मजदूरों का पलायन भी। समाजवादी इस क्रम को इंटरनल कालोनी वाले तर्क से समझाने की कोशिश करते थे। चुनाव के वक्त नेताओं और भाग्य-विधाताओं को इन मजदूरों की याद इसलिए आती है, क्योंकि इनका वोट है।

चुनावी लोकतंत्र में वोट इतना बड़ा है कि आसानी से कल्पना नहीं होती, हालांकि इसी वोट को संदेहास्पद बनाने का जतन भी हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर यह अधिकार न होता तो इन मजदूरों की सुध लेने का होश किस नेता और अधिकारी को रहता। वर्षों पहले राजीव गांधी की सरकार ने एक 'अंतर राज्य प्रवासी मजदूर कानून' बनाकर कुछ चीजें व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। वह बात जाने कहां पीछे छूट गई है। इसमें अपने प्रांत से बाहर जाने वाले मजदूरों के पंजीकरण की बात थी। अगर सही संख्या सामने आ जाए तो कोई भी सरकार और नेता इनकी उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकता। करोना की तालाबंदी में इन लाखों मजदूरों की जो दुर्गति हुई थी, वह भी थमती।

इस लेख का प्रयोजन चुनाव और मजदूरों की आवाजाही बढ़ाने या तकलीफों को बताने का नहीं है। हम जानते हैं कि लंबे इंतजार और सात-आठ साल की देरी से अभी जनगणना का काम शुरू हुआ है। घर गिनती से शुरुआत हुई है। अभी तक अपने यहां मजदूरों के पलायन का कोई ढंग का या अधिकृत आंकड़ा नहीं है। जब घर-घर जाकर सबको गिनने का क्रम चल रहा है तो इस श्रेणी को भी पर्याप्त महत्व देकर अलग स्थान दिया जाए। यह काम किसी 'आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस' से नहीं होगा, घर-घर जाकर ही होगा। अपने यहां जनगणना लगातार दस साल पर हुई है, सिर्फ इसी बार क्रम तोड़ा गया है।

उन कारणों में न भी जाएं और मोदी सरकार को आंकड़ों से डरने वाला न भी बताएं, तो यह कहना जरूरी है कि जब पचीसों पैमाने वाले आँकड़े जुटाए जा रहे हैं तो यह आंकड़ा भी जुटाया जाए, मजदूरों से संबंधित आँकड़े भी लिए जाएं। इन दो मामलों में काफी घालमेल है। मजदूरों के आंकड़ों में 'नेशनल सैंपल सर्वे' और जनगणना के आंकड़ों में भारी अंतर है और सरकार भी 'पीएफ' के खातों की संख्या देखकर मजदूरों की संख्या बताने का हास्यास्पद प्रयास करती है। प्रवासी मजदूरों के मामले में तो पूरा डिब्बा गोल है। सिर्फ अटकलों के आधार पर और वोट देखकर इनकी संख्या के बारे में अंदाजा लगाया जाता है।

संख्या जाने बगैर आर्थिक योजनाओं में प्रवासियों को उचित या अनुचित स्थान या महत्व की बात कैसे सोची जा सकती है? उनके मरने और जन्म लेने वालों तक के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उनकी कमाई को वापस घर तक पहुंचाना आज के युग में भी इतनी नाटकीयता और लूट से भरा है कि उस पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी कानून से लेकर परदेश की जमीन और भाषा से भिन्न इलाके के जीवन में क्या कुछ मुश्किलें आती हैं, उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। इस बीच हम ये किस्से भी चटखारे लेकर छापते हैं कि केरल में मलयालम की परीक्षा में एक बिहारी मजदूर की बेटी टाप करती है। सिर्फ प्रवासी बन जाने से वहाँ रहना, खाना, पहनना, ओढ़ना से लेकर पढ़ाई तक का काम कितना मुश्किल हो गया है इसकी कल्पना मुश्किल है। लोकतंत्र है तो संख्या और अब यह दूसरी ताकत भी तभी हासिल होगी जब पहला काम हो जाएगा। इसलिए इस जनगणना में प्रवासी मजदूरों की गिनती जरूर होनी चाहिए। लोकतान्त्रिक शासन हो तो संगठित जमातों की 'बारगेनिंग पावर' को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। (सप्रेस)

तरबूज-ख़रबूज़ को खा गए बांध व अवैध रेत खनन

मुद्दा

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

भारत की नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने सभ्यता, संस्कृति और कृषि को भी आकार दिया है। मध्य भारत की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के किनारे कभी तरबूज और खरबूज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। यह खेती न केवल किसानों की आय का महत्वपूर्ण साधन थी, बल्कि स्थानीय परंपराओं और खान-पान का भी अभिन्न हिस्सा थी। आज यह खेती धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ चुकी होकर विलुप्त होने की कगार पर है। नर्मदा के तटों पर रेतिली भूमि पाई जाती है, जो तरबूज और खरबूज की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।

नर्मदा नदी पर बने बांधों से न केवल सभ्यता संस्कृति प्रभावित हुई है ,बल्कि किसानों की बेशक़ीमती खेती की ज़मीन भी डूब में गई है तो घर परिवार आँगन भी छिन लिया साथ साथ ही मछुआरों की आजीविका तो दूसरी ओर ख़रबूज़ तरबूज़ की खेती को निमाड़ के क्षेत्र के साथ महाकौशल के क्षेत्र को भी लील लिया है ,परम्परागत रूप से नदी की रेत पर होने वाली यह खेती नदी की बाढ़ से नहीं बांधों के बेक वॉटर से प्रभावित हुई है, तो बचे रकबे को अवैध रेत खनन ने निगल लिया,जिसके चलते कहार माँझी समाज के सैकड़ों परिवारों पर आजीविका का संकट बरसों पहले आ गया लेकिन सरकारों ने आज तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की,जबकि नदी संरक्षरण के नाम पर कई सालों से बड़ी राशि खर्च की जा रही है। मप्र की जीवनदायनी मानी जाने वाली नर्मदा नदी के दोनों किनारों के कई ग्रामों के साथ अनूपपुर से लगाकर आलिराजपुर तक पंद्रह ज़िले शामिल हैं,इन ज़िलों में परंपरागत रूप से माँझी कहार समाज के लोग ख़रबूज़ तरबूज़ की खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे साथ ही मत्स्याखेट भी उनकी पुश्तैनी आजीविका रही है,बांधों के बनने के बाद से नर्मदा नदी के किनारे होने वाली ख़रबूज़ तरबूज़ की खेती धीरे-धीरे पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ में पूरी तरह लुप्त हो गई है कहार माँझी समाज की युवा पीढ़ी ने तो अपने परम्परागत व्यवसाय को देखा भी नहीं होगा।

भारत की नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने सभ्यता, संस्कृति और कृषि को भी आकार दिया है। मध्य भारत की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के किनारे कभी तरबूज और खरबूजे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। यह खेती न केवल किसानों की आय का महत्वपूर्ण साधन थी, बल्कि स्थानीय परंपराओं और खान-पान का भी अभिन्न हिस्सा थी। आज यह खेती धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ चुकी होकर विलुप्त होने की कगार पर है। नर्मदा के तटों पर रेतिली भूमि पाई जाती है, जो तरबूज और खरबूजे की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। कुछ साल पहले तक कहार माँझी समाजजन नर्मदा नदी के किनारे की इस उपजाऊ रेत में बिना किसी रासायनिक उर्वरक के प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे। यह खेती पूरी तरह मौसमी होती थी और मार्च से जून के बीच इन फलों की भरपूर पैदावार होती थी।अपने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बीज बोते थे। नर्मदा का जलस्तर जैसे-जैसे घटता, वैसे-वैसे नई भूमि खेती के लिए उपलब्ध होती जाती। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चक्र के अनुरूप थी और इसमें पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता था।तरबूज और खरबूजे की खेती से को अच्छा

लाभ मिलता था। स्थानीय बाजारों में इन फलों की मांग अधिक रहती थी, जिससे इन्हें स्थिर आय प्राप्त होती थी। इसके अलावा, यह खेती ग्रामीण रोजगार का भी एक बड़ा स्रोत थी।

नर्मदा नदी पर बरगी से लगाकर सरदार सरोवर तक बने बांधो के चलते कई ज़िलों में नर्मदा नदी के बेकवॉटर के कारण नदी तट छ माह से लगाकर आठ माह तक जलमग्न रहते है साथ ही साथ अनेक नदी तट परो अवैध रेत खनन के चलते ये किनारे परम्परागत खेती के अनुकूल नहीं रह गये जिसके चलते कहार माँझी समाजजनों ने परम्परागत खेती को छोड़ दिया है मात्र कुछ साधन सम्पन्न समाज जन जिनके पास खेती की ज़मीन थी वे नदी किनारों को छोड़कर खेतों में इसका उत्पादन कर रहे है,वहीं दूसरी ओर इनके पारम्परिक मत्स्याखेट के व्यवसाय भी प्रभावित हुए है ,नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ज़िले सहित अन्य ज़िले में मत्स्याखेट के लिये नीलामी कर देने से अब व्यापारियों का दबदबा मत्स्याखेट में बढ़ गया है,वे व्यवसायिक मछुआरों को मानदेय के आधार पर लाकर मत्स्याखेट कर रहे है जिसके चलते स्थानीय मछुआरे की आजीविका पर संकट आ गया है। नरसिंहपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अमर नोरिया के अनुसार महाकोशल क्षेत्र मे जबलपुर तक परंपरागत तरबूज खरबूज की खेती हमारे पूर्वज करते थे,लेकिन कई सालो से बरगी बांध व अवैध रेत खनन ने हमारी आजीविका को छीन लिया है,वहीं बड़वानी जिले के नर्मदा किनारे बिजासन के रहने वाले जितेंद्र मांझी बताते हैं आठ से दस माह तक नर्मदा के किनारे बेकवॉटर मे रहते तो परंपरागत खेती हमारे लिए संभव नहीं रह गई है। कहार मछुआरा समाज के द्वारा अपनी माँगों को लेकर अनेकों बार धरना प्रदर्शन किए लेकिन उन्हें आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं मिला, जहां सरकार ने स्थानीय मछुआरों को ज़िले के तालाबों में मछली पालन में प्राथमिकता देने की बात कही थी वह भी पूरी नहीं हुई,दूसरी ओर बजरी माफिया दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर नर्मदा के किनारे व तल की सफाई (खुदाई) कर रहे अपने राजनीतिक आकाओं की मदद से।

'यह कहां लिखा है ?' ऐसे सवाल बेमानी है

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

बहुत सी ऐसी बातें होती है जो न तो धर्म शास्त्रों में उल्लेखित होती है और न ही संविधान में। लेकिन उसका लौकिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से पालन करना आवश्यक समझा जाता है। इस तथ्य को आम नागरिक भली-भांति समझते हैं और इसका परिपालन भी किया करते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक बिरादरी का सवाल है, तो लगभग हर किसी दल एवं उसके अनुयायियों के अपने-अपने पूर्वाग्रह है। हालांकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर तो आपत्तिनहीं की जा सकती लेकिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धर्म एवं संविधान को मोहरा बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान दौर में राजनीतिक पूर्वाग्रह की प्रबलता कुछ इस कदर दिखाई देती है कि बिना धर्म या संविधान को जाने, धर्म और संविधान के प्रबल पैरोकार के रूप में स्वयं को स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। इसके चलते धर्म का 'मूल तत्व' और संविधान का 'मूल भाव' अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आम नागरिकधर्म की दृष्टि से धर्मशास्त्र को तवज्जो देता है और राष्ट्र धर्म की दृष्टि से संविधान के अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार रखता है। दरअसल यह कोई आवश्यक नहीं है कि धर्मशास्त्र और संविधान में जो कुछ उल्लेखित है, वही अपने आचरण और व्यवहार में लाया जाएं और उसके अतिरिक्त कुछ किया या सोचा ही नहीं जाएं।

वास्तव में धर्म एवं संविधान की मूल आत्मा के स्वाभाविक निहितार्थ के अनुरूप आचरण और व्यवहार तो सामान्य रूप से अपेक्षित होता ही है। यह समझना ठीक नहीं कि जो कोई धर्मशास्त्र या संविधान में लिखा ही नहीं गया है, वह किया ही नहीं जाएं। यदि इस प्रकार की ही सोच रखी जाएगी तो क्या तमाम रीति रिवाज परंपरा जिसका उल्लेख किसी शास्त्र में नहीं है, क्या सिरे से ही नकारी जा सकती है? दरअसल यह संभव नहीं है कि आदमी का हर क्रियाकलाप, आचरण और व्यवहार को लेकर एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का धर्मशास्त्र या संविधान में उल्लेख हो सके। वास्तव में हमें धर्मशास्त्र और संविधान के मूल भाव को पकड़ने की आवश्यकता है।

लेकिन इस समय बिना कुछ सोचे-समझे धर्मशास्त्र एक संविधान के प्रति अपनी नादानियों को भी राजनीतिक वर्चस्व की भूख के चलते तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। हालांकि निरंतर परिवर्तित दौर में देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप किसी आचरण और व्यवहार को मान्यता मिल सकती है, लेकिन ऐसा सकारात्मक रूप से हो, यह अपेक्षित होता है। लेकिन इस समय राजनीतिकपूर्वाग्रह के चलते धर्मशास्त्र और संविधान के हवाले से अपनी जिद और जुनून की पूर्ति की जाने लगी है। इस समय राजनीतिक मानसिकता के चलते बात बात पर विशेष रूप से धर्मशास्त्र एवं संविधान के हवाले से यह कहा जाने लगा है कि ' यह कहां लिखा है?'

यह स्थिति एक प्रकार से धर्म एवं राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठा और विश्वास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित करने का कारण बन सकती है। वैसे यह कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का आचरण और व्यवहार तब ही उचित करार दिया जाए जबकि ऐसे आचरण और व्यवहार का उल्लेख किसी शास्त्र में किया गया हो। इस संदर्भ में यह चिंताजनक स्थिति है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त पूर्वाग्रही मानसिकता के चलते बेबुनियाद मुद्दे हवा में उछाले जा रहे हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन धर्मशास्त्र और संविधान का हवाला देकर अपने पूर्वाग्रहों को बल देना, बहुत चिंताजनक है।

कितनी विचित्र बात है कि चाहे न धर्म को और न ही संविधान के मूल तत्व को रत्ती भर भी समझा हो। लेकिन राजनीतिक दिमाग इस कदर चलने लगा है कि बार-बार धर्मशास्त्र और संविधान का हवाला दे देकर ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि धर्म और संविधान के खेवईया हम ही हैं। कुल मिलाकर आम नागरिकों को राजनीतिक बिरादरी में ऐसे तत्वों को चिन्हित कर लेना चाहिए जो धर्मशास्त्र और संविधान की आड़ में अपने राजनीतिक मनोरथ की पूर्ति के लिए अपने मूल धर्म तथा राष्ट्र धर्म के प्रति गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

चिंतन बड़ी एबली चीज होती है !

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बैठक कहो, अधिवेशन कहो, मंथन या शिविर बोलो, बात कमोबेश एक ही है , चिंतन। चिंतन का ऐसा है सिरिमानजी कि इसको खुद ही करना पड़ता है। और करने का ऐसा है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। राजनीति में यही ऐसा काम है जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम है। नहीं करो तो खतरा और करो तो उससे भी बड़ा खतरा। अगर चिंतन करने वालों ने निष्कासित होने के बाद अपनी पार्टी बनाई होती तो कइयों ने बना ली होती। बनाना चाहे तो लोग बिना चिंतन के भी पार्टी बना लेते हैं। लेकिन सिरिमानजी चिंतन बड़ी एबली चीज होती है। एक बार किसीको चिंतन की लत पड़ जाए तो किसी 'चिंतन-मुक्ति शिविर' से भी लाभ नहीं होता। पार्टी की मजबूती के लिए कइयों को मना किया जाता है कि आप कृपया अपना दिमाग नहीं चलाएं, किन्तु वो अपना दिमाग दौड़ाए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि पार्टी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर .... अंत में खदेड़ देती है। नतीजे में बस ये चर्चा रह जाती है सिरिमानजी, कि चिंतन से बचो और पार्टी में बने रहो।

घटना का सांप सफलता पूर्वक निकल जाए, तो रह गई लकीर को पीटना चिंतन करना कहलाता है। यह एक तरह का 'सेफ-चिंतन' होता है। कुछ लोग इसे राजनीतिक चिंतन भी कहते पाए जाते हैं। अभी आपको बताया कि चिंतन बड़ी एबली चीज होती है। करो चाहे नहीं करो परंतु लोगों को मालूम चलना चाहिये कि पार्टी चिंतनशुदा है। राजनीति में चिंतन मांग का सिंदूर होता है , और सिंदूर से न मेडिकल जांच होती है न चरित्र का प्रमाण-पत्र बनता है। लेकिन लोकतंत्र में चिंतन की साख होती है। कुछ परंपरावादी वोट साख के कारण भी मिलते देखे गए हैं।

कथाओं से पता चलता है कि हमारी विभूतियां जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में बैठ कर चिंतन किया करतीं थी। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा ! आजकल मीडिया का जमाना है , उन्हें मैनेज करने की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। चिंतन हुआ लेकिन चर्चा नहीं हुई तो फायदा ही क्या ! और फिर गलती से विकास बहुत हो गया है। जंगल कट गए हैं , विभूतियां भी पांच सितारा जीवन जीने लगी हैं। चिंतन के लिये गुंजाइश नहीं के बराबर बची है। वो तो अच्छा है कि अनेक विभूतियों को कब्ज की समस्या है और कमोड़ पर बैठे वे दिनभर का आवश्यक चिंतन इस दौरान कर लेते हैं वरना विचार की भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाती। किन्तु ऐसा नहीं है कि प्रयास किये जाएं और किसी समस्या का हल न मिले। गुफाएं-कंदराएं न मिलें तो कई बार तंबू में चिंतन कर लेने का रिवाज हो गया है। तंबू-चिंतन में सुविधा ज्यादा होती है और समय भी कम लगता है। वैज्ञानिक शोधों ने बताया है कि चिंतन तंबुओ में सुरक्षित होता है। दरअसल तंबुओं के कान नहीं होते, दीवारों के होते हैं।

एक बात और है सिरिमानजी, आप देखिये कि देश इस समय आलोचना के संकट से भी गुजर रहा है। वैसे गुजरने को तो दाल, चावल, तेल, शकर, गेंहू, बिजली, गैस जैसी अनेक चीजों की महंगाई से भी गुजर रहा है। लेकिन चिंतन-शो में लगाए रखो तो जनता धैर्य रखती है और संकट बेशरमी से अपने आप गुजर जाता है। और अगर नहीं गुजरता तो जनता को उस संकट की आदत पड़ जाती है।

चिंता चिंतन से बड़ी चीज होती है। देश की चिंता एक अलग मामला है उसके लिये बुद्धिजीवीनुमा काफी सारे लोग हैं जो प्रायः बिना कब्ज की शिकायत के भी चिंतन करते हैं। इसीलिये राजनीतिक दल बुद्धिजीवियों से श्री-सम्मान वगैरह दे-दिलाकर, सुरक्षात्मक और आवश्यक दूरी बनाए रखते हैं। चिंतन बड़ी एबली चीज होती है सिरिमानजी, देश को लगना चाहिये कि चिंतन देश के लिये किया जा रहा है , फिर चाहे कमोड-साधना के लिए किया गया चिंतन ही क्यों न हो। शिविरों में सामूहिक चिंतन होता है।

सर्कस या मेले में आपने मौत का कुंआ देखा होगा, उसमें आदमी मोटर सायकल चलाता है। सिरिमानजी हमने पूछा उससे कि आप इतनी तेज मोटर सायकल कैसे चला लेते हैं !! तो वह बोला कि मौत के कुंए में ट्रेफिक-सिगनल नहीं होता है, और आप चाहे जितना भी तेज चलिये कुंए से बाहर नहीं निकलते है , देखने वालों के रोंगटे भले ही खड़े हो जाएं। शिविरों का भी यही महत्व है सिरिमानजी, रोंगटे खड़े करना। चिंतनिये इतनी जोर का चिंतन करें कि जनता के रोंगटे खड़े हो जाएं तो चिंतन सफल हुआ समझो। चिंतन के कुंए में मोटरसायकल दौड़ाई तिरिभिन्नाट और रहे वहीं के वहीं। इधर शिविर में चिंतन भी हुआ तिरिभिन्नाट और रहे वहीं के वहीं। इसीलिये तो कहा है सिरिमानजी कि चिंतन बड़ी एबली चीज होती है।

जलवायु राजनीतिः महाड़ सत्याग्रह, समान अधिकार और गरिमा

अंबेडकर का चिंतन व्यावहारिक समाधान की ओर उन्मुख था। उनके अनुसार, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी नीतियाँ बनाए जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के साथ हुए पारिस्थितिक अन्याय को कम कर सकें। आज एआई के दौर में भी स्थिति बहुत अधिक बदली नहीं है। वंचित और आदिवासी समुदाय भूमि हीनता, जल संकट और पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। उनकी बस्तियाँ अक्सर बाढ़-प्रभावित, सूखा-ग्रस्त या कम उपजाऊ क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जिससे उनकी आजीविका और जीवन-स्तर दोनों प्रभावित होते हैं।

अंबेडकर दर्शन
प्रो. अस्मिता सिंह
लेखक शोधार्थी हैं।

बाबा साहब लोकतंत्र को बड़े दिलचस्प रूप में देखते थे वे इसे जीवन को व्यवस्थित करने का नैतिक और सामाजिक आदर्श मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र तब ही सार्थक है जब वह समाज के हर व्यक्ति के जीवन में समानता और स्वतंत्रता के रूप में अनुभव किया जाए। इसीलिए बाबा साहब लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते है। यदि लोकतंत्र को जीवन शैली माना जाए, तो यह स्वाभाविक है कि प्राकृतिक और पारिस्थितिक संसाधनों के वितरण में भी वही लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू हों। बाबा साहब स्पष्ट रूप से मानते थे कि वन, भूमि और जल जैसे संसाधन किसी विशेष वर्ग के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, बल्कि ये समाज की साझा धरोहर हैं, जिन पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए।

उनकी दृष्टि में पारिस्थितिक असंतुलन सामाजिक असमानता का परिणाम है। जब समाज में ऊँच-नीच, विशेषाधिकार और बहिष्करण की प्रवृत्ति होती है, तो उसका प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भी दिखाई देता है। परिणामस्वरूप, एक वर्ग संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है, जबकि वंचित समुदाय उनकी मूलभूत पहुँच से भी वंचित रह जाते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव है जब प्राकृतिक संसाधनों तक सभी वर्गों की समान और सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित की जाए। यह दृष्टिकोण उनके व्यापक सामाजिक न्याय के सिद्धांत का ही विस्तार है।

अंबेडकर का चिंतन व्यावहारिक समाधान की ओर उन्मुख था। उनके अनुसार, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी नीतियाँ बनाए जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के साथ हुए पारिस्थितिक अन्याय को कम कर सकें। आज एआई के दौर में भी स्थिति बहुत अधिक बदली नहीं है। वंचित और आदिवासी समुदाय भूमि हीनता, जल संकट और पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। उनकी बस्तियाँ अक्सर बाढ़-प्रभावित, सूखा-ग्रस्त या कम उपजाऊ क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जिससे उनकी आजीविका और जीवन-स्तर दोनों प्रभावित होते हैं।

दरअसल केन बेतवा लिंक हो या मध्यप्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, यह पारिस्थितिक संतुलन एवं वंचित वर्ग के बीच संबंधों पर बहुत गंभीर विचार की आवश्यकता को सामने लाते हैं। रातापानी में नीलगढ़ और धुँधवानी सहित लगभग 10 गांवों के सैकड़ों परिवारों का प्रस्तावित विस्थापन तथा केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की स्थिति यह संकेत है कि विकास और संरक्षण की प्रक्रियाओं के साथ-साथ मानव जीवन, आजीविका और सांस्कृतिक जुड़ाव के आयामों पर भी समान संवेदनशीलता अपेक्षित है।

यह स्थिति हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि जिन समुदायों ने लंबे समय तक प्रकृति के साथ सहअस्तित्व में जीवन जिया है, उनके अनुभव और अधिकार भी इन प्रक्रियाओं का अभिन्न हिस्सा बनें। जंगल से शहर के किनारे पहुंचना हमेशा विकास नहीं होता, कई बार यह विस्थापन से उत्पन्न असुरक्षा और पहचान के संकट को जन्म देता है। इसी संतुलन में पारिस्थितिक न्याय की वास्तविक भावना निहित है, जहाँ पर्यावरण संरक्षण और मानवीय गरिमा दोनों एक साथ आगे बढ़ सकें।

बाबा साहब के विचार आज की पर्यावरण राजनीति में भी समान रूप से प्रासंगिक है। पारिस्थितिक संकटों का समाधान तकनीकी उपायों, संसाधनों के समान वितरण और सामाजिक भागीदारी के विस्तार से ही संभव है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों और आंदोलनों के अनुभव यह बताते हैं कि जब हाशिए पर खड़े समुदायों को पर्यावरणीय निर्णय-प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है, तब न्याय भी सुनिश्चित होता है और संरक्षण के प्रयास भी अधिक प्रभावी होते हैं।

बाबा साहब मानव मुक्ति और प्रगति के लिए पारिस्थितिकी का संरक्षण और उपयोग करना चाहते थे। वे अपनी पुस्तक 'बुद्ध और उनका धम्म' में इस बात को बहुत सहज और दिलचस्प रूप से स्पष्ट करते है कि भारतीय पर्यावरण चिंतन जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक या पारंपरिक हो इसके भौतिक और नैतिक आयाम भी हैं। बुद्ध के समय से लेकर अपने समय तक, अंबेडकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भारतीय लोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत चिंतित हैं यह एक आध्यात्मिक कर्तव्य के रूप में तो है ही साथ ही मानव समाज के एक नैतिक दायित्व के रूप में भी उपस्थित है।

आगे वह लिखते हैं कि जब तक आप पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक बहुत ही कुशल और प्रभावी नीतिगत ढांचा तैयार नहीं करते, तब तक उनका इष्टतम और टिकाऊ उपयोग संभव नहीं । वे एक ऐसे पारिस्थितिक शासन की कल्पना करते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो और जिसमें केवल नीतियाँ ही नहीं, बल्कि समाज की सोच में भी परिवर्तन आवश्यक हो। उनके विचार में जब तक लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आता, तब तक कोई भी पर्यावरणीय व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती। वे एक ऐसी नैतिक पर्यावरण-दृष्टि प्रस्तुत करते है, जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग हो, इतना ही उपयोग, जितना उनकी निरंतरता को बनाए रख सके।

आज के जलवायु संकट को यदि अंबेडकरवादी दृष्टि से देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि इसका समाधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों विशेषकर समानता और न्याय पर ही आधारित हो सकता है। यही सिद्धांत आज वैश्विक स्तर पर 'जलवायु राजनीति' में भी उभर कर सामने आ रहा है। विशेष रूप से जल के प्रश्न पर उनका दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट था। महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने यह स्थापित किया कि जल समान अधिकार और गरिमा का प्रश्न है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जल तक समान पहुँच के बिना न तो सामाजिक न्याय संभव है और न ही लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना। प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुँच ही लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी है।

अंततः, आज के जलवायु संकट के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम अत्यधिक उपभोक्तावादी संस्कृति को हतोत्साहित करते हुए संसाधनों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग की दिशा में आगे बढ़ें। जब हम अपने साथी मनुष्यों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव विकसित करते हैं, तभी एक वास्तविक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी जा सकती है। यही मानवीय और समावेशी दृष्टिकोण हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है, जहाँ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय दोनों का संतुलित समाधान संभव हो।

भूतपूर्व होना या अभूतपूर्व बने रहना !

विचार
अनिल त्रिवेदी
अभिभाषक एवं स्वतंत्र लेखक

भूतपूर्व होना यानी आकस्मिक रूप से या पदावधि समापन से जीवन में आयी बीती यादों या बातों को अपने शेष बचे जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है। अभूतपूर्व होने या बने रहने में किसी याद या बात या पद के मिलने या निर्वाचित होने की अनिवार्यता का कोई लेना-देना ही नहीं है! भूतपूर्व होना यानी बहुत मशक्कत से या संयोगवश हांसिल पद या पद से हांसिल अधिकार दायित्व,सुख, सुविधा, सुरक्षा और लाव लश्कर या बंगले का जीवन से यकायक निकल जाने जैसा जीवन का शेष कालखंड! इसे क्या कहा जाये? शायद इस विशेषण या स्थिति को एक तरह से अतीत की व्यवस्थागत रूप से हासिल की गयी पदेन उपलब्धि का आजीवन वर्तमान पर हमेशा के लिए ठहर जाना ही तो माना जा सकता है! अच्छे खासे पदासीन थे अब अचानक कालक्रम में पदावसान हो गया, पद मुक्त हो गये याने भूतपूर्व हो गये। मनुष्य यदि खालिस मनुष्य रहे तो आजीवन अभूतपूर्व ही रहेगा! कोई भी व्यक्ति संयोग वश या राज्य की कृपा से या अन्यथा भी किसी तरह अपने पुरूषार्थ से या परिस्थिति वश किसी पद पर निर्वाचित होकर या बिना निर्वाचित हुए भी पहुंच जाता है या पद हासिल कर लेता है तो वह अपने शेष जीवन काल में ही भूतपूर्व होने की संभावना को स्वयं ही अर्जित कर लेता है। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में कोई पद स्वयं के पुरूषार्थ से या अन्यथा संयोग वश या किसी अन्य की कृपा से हांसिल नहीं किया है तो ऐसा मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी भूतपूर्व नहीं हो सकता है। भूतपूर्व होने के लिए अपने जीवन में कोई पद हासिल करना आवश्यक है।

मनुष्य के अंदर अपने मूल स्वरूप में उसके जो जन्मजात नैसर्गिक गुण या विशेषता मौजूद रहती है वे उसे कभी भी अपने जीवन काल में भूतपूर्व होने का अवसर या अधिकार नहीं देती है। भूतपूर्व होना एक ऐसा विशेषण हैं जो किसी भी मनुष्य को अपने भूत काल या अतीत के गौरव का स्मरण दिलाता है। अभूतपूर्व होने के गुण या तो मनुष्य में जन्मजात प्रतिभा के रूप में सदैव या जन्मना मौजूद रहते हैं। पर मनुष्य को अपने जीवन काल में उन गुणों को यथा सम्भव अपने अंदर अभिव्यक्त करना होता है। जैसे आप गायन या कंठ संगीत में सिद्ध हस्त है या बांसुरी वादन में महारथ हासिल कर चुके हैं तो आपको उसे सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होता है तब आपको अभूतपूर्व माना जाने लगता हैं।आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत हैं तो आपको उस विलक्षण स्मरण शक्ति को अन्य लोगों के समक्ष व्यक्त करना होता है तभी लोग आपकी स्मरण शक्ति का लोहा मानते हैं।आप बहुत बढ़िया चित्रकार है तो आपको अपने चित्रों से लोगों के मन में यह भाव अपनी चित्र कला के माध्यम से विकसित करना होता है।आपकी साधना और समर्पण लोगों के मन में यह भाव जगाता है कि आप अद्भुत चित्रकार, गायक या किसी अन्य क्षेत्र में महारत हासिल किये हुए हैं। आपकी वाणी, अभिव्यक्ति और बोलने का लहजा आपको अभूतपूर्व वक्ता बना देता है। लोग, श्रोता या गुणी जन आपको यह विशेषण प्रदान करते हैं।आप स्वयं अपने बारे में ऐसा विशेषण नहीं लगा सकते हैं यदि आपने स्वयं अपनी विशिष्ट पहचान या कला मर्मज्ञ होने को स्वयं के मुख से अभिव्यक्त किया तो इसे आपकी कमजोरी या प्रसिद्धि पाने की क्षुद्र लालसा माना या समझा जाता है। अपने गुणों को अपने जीवन में अपनी लेखनी, चित्र कला,या वाणी से आप स्वतः व्यक्त तो कर सकते हैं पर अपना बखान स्वयं ही नहीं कर सकते हैं।

भूतपूर्व भी अभूतपूर्व हो सकता है पर अभूतपूर्व कभी भूतपूर्व नहीं होता हैं ,आजीवन अभूतपूर्व ही रहता हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में जो स्थिति या दर्जा हासिल होता है वह बदल जाये तो ऐसा बदलाव आपको एकाएक वर्तमान से इतिहास में स्थापित कर देता है। मनुष्य मूलतः मनुष्य ही हैं। मनुष्य में कोई विशेषण नहीं है। विशेषण मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने नहीं देता। विशेषण मनुष्य की संभावना या विस्तार को सीमाबद्ध कर देता है। मनुष्य प्रकृति की अनन्त संभावना वाली एक ऐसी जीवित ऊर्जा हैं जो प्रकृति को अपनी सोच और समझ से अपने चिंतन, मनन और सृजनशीलता के अधीन करने के सपने के साथ जीवन जीते रहने का सपना साकार करने हेतु प्रागैतिहासिक काल से आज तक निरन्तर संघर्षरत हैं। संघर्ष और जीवन सनातन काल से अभूतपूर्व है और रहेगें।जीवन और जीव का अनन्त जीवन प्रवाह कभी खत्म न होने वाला एक ऐसा सिलसिला हैं जो प्रकृति में अभूतपूर्व रुप से गतिशील बना हुआ है या यह सिलसिला कभी भी भूतपूर्व नहीं हो सकता हैं। जीवन अभूतपूर्व है पर इस जगत का सबसे बौद्धिक मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी ही बनाई व्यवस्था या कालक्रम में अभूतपूर्व से एकाएक भूतपूर्व हो जाता हैं! यही जीवन की ऊर्जा का काल क्रमानुसार आनन्दमयी पर अभूतपूर्व खेल है!

गुम हुई स्वर-संसार की अनुपम विरासत

आशा भोंसले
एकता शर्मा
(लेखिका और समीक्षक)

भारतीय सिनेमा और संगीत जगत ने एक ऐसी आवाज को खो दिया है, जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। आशा भोसले का निधन केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि एक युग का अवसान है। उनकी आवाज़ में जो विविधता, जीवंतता और प्रयोगधर्मिता थी, वह उन्हें अपने समय की अन्य गायिकाओं से अलग बनाती है।

भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में आशा भोसले का नाम अद्वितीय प्रतिभा और बहुआयामी स्वर-साधना के लिए सदा स्मरणीय रहेगा। 12 हजार से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ देने वाली इस महान गायिका ने केवल संख्या के स्तर पर ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता और विविधता के स्तर पर भी नए मानदंड स्थापित किए। अक्सर उन्हें लता मंगेशकर की छोटी बहन के रूप में पहचाना गया, लेकिन आशा भोसले ने अपनी एक अलग पहचान गढ़ी, ऐसी पहचान, जो साहसिक प्रयोगों, आधुनिकता और लयात्मक चंचलता से भरी हुई थी। जहां लता मंगेशकर का स्वर शुद्धता और माधुर्य का प्रतीक था, वहीं आशा भोंसले की आवाज में जीवन के विविध रंग, मस्ती, दर्द, नजाकत और शरारत सभी एक साथ झलकते थे।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी हर शैली में खुद को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता। चाहे वह ग़ज़ल हो, पॉप हो, क्लब सॉन्ग हो या शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। आरडी बर्मन के साथ उनकी जुगलबंदी ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई दिशा दी। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा जैसे गीत आज भी उनकी प्रयोगशीलता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसके विपरीत, जब उन्होंने ग़ज़ल गायीं, तो उनकी आवाज़ में एक गहरी संवेदनशीलता और ठहराव दिखाई देता है। खय्याम के संगीत निर्देशन में फिल्म 'उमराव जान' के गीतों ने यह सिद्ध किया कि आशा भोसले केवल चंचल गीतों की गायिका नहीं, बल्कि गंभीर और शास्त्रीयता से परिपूर्ण गायन में भी समान रूप से दक्ष हैं।

उनकी आवाज़ में एक विशेष 'अभिनय तत्व' भी था वे केवल गाती नहीं थीं, बल्कि हर गीत को जीती थीं। यही कारण है कि उनके गीतों में भावनाओं की प्रामाणिकता सहज ही महसूस की जा सकती है। वे जिस अभिनेत्री के लिए गाती,उनकी शैली और व्यक्तित्व के अनुरूप अपने स्वर को ढाल लेती थीं। यह गुण बहुत कम गायकों में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत जीवन में भी आशा भोसले का सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी इन कठिनाइयों को अपनी कला पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया और निरंतर आगे बढ़ती रहीं। यही जिजीविषा उनके गायन में भी झलकती है एक ऐसी ऊर्जा, जो कभी थमती नहीं। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तब यह महसूस होता है कि उनकी कमी को भर पाना लगभग असंभव है। बदलते समय के साथ संगीत की शैली और तकनीक भले ही बदल जाए, लेकिन आशा भोसले जैसी बहुआयामी और निर्भीक कलाकार की पुनरावृत्ति होना कठिन है। उनकी आवाज़ अब भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनके गीत हमेशा जीवित रहेंगे। हर उस दिल में, जो संगीत को केवल सुनता नहीं, बल्कि महसूस करता है। आशा भोसले केवल एक गायिका नहीं थीं, वे भारतीय संगीत की आत्मा थीं और यह आत्मा कभी नहीं मिटेगी।

कॉर्पोरेट ढाँचे में छिपा शोषण तंत्रः विचारधारा, कानून और समाज की चुनौती

कार्य संस्कृति
डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

एक शिकायत से प्रारंभ होकर कई एफआईआर तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि समस्या आकस्मिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक थी। जब कई महिलाएँ एक के बाद एक सामने आती हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव बन जाता है—एक ऐसा अनुभव, जिसे लंबे समय तक दबाकर रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वह है शोषण की एक सुनियोजित कार्यप्रणाली। प्रारंभ में विश्वास अर्जित किया जाता है—सहकर्मी के रूप में, मित्र के रूप में, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो करियर में मदद कर सकता है।

भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र लंबे समय से आधुनिकता, प्रगति और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता रहा है। चमकदार कार्यालय, उच्च वेतन और वैश्विक कार्य संस्कृति के बीच यह धारणा गहराई से बैठ गई कि यहाँ सुरक्षा, समानता और नियम सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किंतु हाल के घटनाक्रमों ने इस छवि को गंभीर चुनौती दी है। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए प्रकरण ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिकता के इस आवरण के पीछे एक ऐसा तंत्र भी विकसित हो सकता है, जहाँ शोषण, दबाव और अपराध व्यवस्थित रूप से संचालित हों।

यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों के आपराधिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस गहरे संकट की ओर संकेत करता है, जहाँ संस्थागत संरचनाएँ अपने मूल दायित्वों से विमुख हो जाती हैं। एक शिकायत से प्रारंभ होकर कई एफआईआर तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि समस्या आकस्मिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक थी। जब कई महिलाएँ एक के बाद एक सामने आती हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव बन जाता है—एक ऐसा अनुभव, जिसे लंबे समय तक दबाकर रखा गया।

इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वह है शोषण की एक सुनियोजित कार्यप्रणाली। प्रारंभ में विश्वास अर्जित किया जाता है—सहकर्मी के रूप में, मित्र के रूप में, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो करियर में मदद कर सकता है। इसके बाद धीरे-धीरे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश किया जाता है, जहाँ भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक प्रभाव के माध्यम से व्यक्ति को निर्भर बनाया जाता है। जब यह निर्भरता स्थापित हो जाती है, तब दबाव, ब्लैकमेल और शोषण का चरण आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में पीड़िता के आत्मविश्वास को तोड़ा जाता है, उसकी पहचान को कमजोर किया जाता है और उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकती।

यह केवल शारीरिक शोषण का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानसिक और वैचारिक नियंत्रण का भी विषय है। जब किसी व्यक्ति की आस्था, उसकी मान्यताओं और उसकी सांस्कृतिक पहचान को लगातार अपमानित किया जाता है, तो वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी कमजोर होने लगता है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा दोनों पर आघात करती है।

इस पूरे मामले में संस्थान की भूमिका भी कठघरे में खड़ी होती है। जब पीड़िताओं ने शिकायत की और उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि 'यह सब सामान्य है,' तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि एक गंभीर संस्थागत विफलता का संकेत है। किसी भी संगठन का मानव संसाधन विभाग केवल प्रशासनिक इकाई नहीं होता, बल्कि वह कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान का संरक्षक होता है। यदि वही विभाग शिकायतों को दबाने लगे या उन्हें महत्वहीन मानने लगे, तो यह पूरे संगठन की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगा देता है।

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 जैसे सशक्त कानून बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता में भी कठोर प्रावधान हैं। फिर भी यदि ऐसे मामले सामने आते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि समस्या कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की है। जब अपराधी यह मान लेते हैं कि वे बच निकलेंगे, तब कानून का भय समाप्त हो जाता है।

यह स्थिति हमें एक गहरे सामाजिक प्रश्न की ओर ले जाती है—क्या हमारे समाज में पीड़ित को न्याय मिलने का विश्वास है? अक्सर देखा जाता है कि पीड़िता को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसे बदनामी का भय सताता है, और वह अपने करियर या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण चुप रहने को मजबूर हो जाती है। यही मौन अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

कॉर्पोरेट संस्कृति का एक अंधकार पक्ष भी इस संदर्भ में सामने आता है। प्रदर्शन, लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में कई बार नैतिकता पीछे छूट जाती है। शक्ति का केंद्रीकरण, पद का दुरुपयोग और आंतरिक राजनीति मिलकर ऐसा वातावरण बना देते हैं, जहाँ शिकायत करना जोखिम भरा हो जाता है। जब संस्थान अपनी छवि बचाने के लिए सच्चाई को दबाने लगता है, तो वह स्वयं अपराध का भागीदार बन जाता है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसकी शक्ति, उसका पद या उसका नेटवर्क कानून से बड़ा है, तब समाज में अराजकता की शुरुआत होती है। कानून का अस्तित्व केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में होता है। यदि उसका भय समाप्त हो जाए, तो कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती।

इस परिस्थिति में समाधान केवल कठोर कानून बनाना नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र को पुनर्गठित करना है। संस्थानों को अपनी आंतरिक संरचनाओं को मजबूत करना होगा, शिकायत निवारण तंत्र को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। कानून को भी त्वरित और प्रभावी बनाना आवश्यक है, ताकि अपराधी को शीघ्र दंड मिले और पीड़ित को न्याय का अनुभव हो।

साथ ही समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, जहाँ पीड़ित को दोषी नहीं, बल्कि साहसी माना जाए; जहाँ शिकायत करना कमजोरी नहीं, बल्कि अधिकार समझा जाए; और जहाँ न्याय केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि वास्तविकता हो।

नासिक का यह प्रकरण केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि क्या हमारा विकास केवल भौतिक है या नैतिक भी। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से नहीं खोजते, तो ऐसी घटनाएँ भविष्य में और अधिक गंभीर रूप में सामने आ सकती हैं।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसके कानूनों में नहीं, बल्कि उनके पालन में होती है। जब तक अपराधी को दंड और पीड़ित को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए समय की माँग है कि हम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उन कारणों को समझें और समाप्त करें, जो ऐसे अपराधों को जन्म देते हैं।

कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित

● 10वीं का एक प्रतिशत कम, वहीं 12वीं का 5 प्रतिशत बढ़ा परीक्षा परिणाम ● प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 10वीं के 5 विद्यार्थी तथा 12वीं में एक छात्रा है शामिल

एस. द्विवेदी, बैतूल। बुधवार सुबह करीब 11 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल भूपेंद्र वरकड़े ने बताया कि वर्ष 2025-26 के हाईस्कूल 10वीं एवं हायर सेकेंडरी 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। जिले में 10वीं कक्षा में कुल 19,759 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 19,337 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 13,999 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार जिले का कुल परीक्षा परिणाम 79.70 प्रतिशत रहा। वहीं 12वीं कक्षा में कुल 14,581 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ, जिनमें से 14,364 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें 8,999 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जिले का कुल परीक्षा परिणाम 74.01 प्रतिशत रहा।

डीईओ बैतूल भूपेंद्र वरकड़े ने बताया कि वार्षिक परीक्षा परिणाम में जिले के अंतर्गत कक्षा 10वी में 5 एवं कक्षा 12वीं से 1 विद्यार्थी ने राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वी में छात्र गुंजन देशमुख ने 495/500 प्राप्तांक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान एवं राज्य में पांचवा स्थान प्राप्त किया, शिवम घोडके नौवा स्थान, पीहू राठौर एवं चंद्रशेखर हुरमाडे ने दसवां स्थान पाया है।

समस्त छात्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल से है एवं यूनिवर्सल स्कूल आमला के छात्र उदित पवार ने आठवा स्थान प्राप्त कर उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा कक्षा 12 वी में महर्षि दयानंद इंग्लिश स्कूल चिचोली की छात्रा कुमारी ऋतुजा देशपांडे ने प्रदेश स्तर में सातवां स्थान प्राप्त किया है । पिछले वर्ष की तुलना में कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में 1 प्रतिशत की कमी एवं कक्षा 12वीं में 5 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष हुई है। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 74.01 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल 12वीं का परीक्षा परिणाम 69.46 प्रतिशत था।

उत्कृष्ट स्कूल के चार और आमला की एक छात्रा प्रदेश प्रावीण्य सूची में शामिल- शहर के प्रतिष्ठित उत्कृष्ट विद्यालय ने फिर प्रदेश के साथ जिले की सूची में उत्कृष्ट जगह बनाई है। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र उदयपुरे ने बताया कि विद्यालय की कक्षा 10वीं के 4 विद्यार्थियों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में जगह बनाई। इसमें कक्षा 10वीं के गुंजन देशमुख पिता सुनील देशमुख ने 495 अंक हासिल कर प्रदेश में पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं आमला यूनिवर्सल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा उदिता पिता गिरधारी पंवार ने 492 अंक लेकर प्रदेश में आठवां स्थान पाया। इसके अलावा प्रदेश की प्रावीण्य सूची में उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल के छात्र शिवम पिता हेमराज खोडके ने 492 अंक लेकर 9वां स्थान, चंद्रशेखर पिता नारायण हुरमाड़े ने 490 अंक एवं पीयू राठौड़ पिता बलराम राठौड़ ने भी 490 अंक हासिल करके प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान हासिल किया।

10वीं-12वीं में शामिल हुए थे 33701 विद्यार्थी – जिले से इस साल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिलाकर 33702 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। डीईओ भूपेंद्र वरकड़े ने बताया कि कक्षा 10वीं में कुल 19337 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें 16204 विद्यार्थी नियमित एवं 3133 स्वाध्यायी विद्यार्थी है। जबकि 9296 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं कक्षा 12वीं में कुल 14364 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें 12159 नियमित विद्यार्थी और 2205 स्वाध्यायी विद्यार्थी है एवं 6683 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है।

इनका कहना है – इस साल कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में एक प्रतिशत की कमी और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 10वीं में जिले के 5 और कक्षा 12वीं की एक छात्रा प्रदेश की टापटेन सूची में शामिल हुई है। इस साल कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम 79.70 और 12वीं का 74.01 प्रतिशत रहा है।

– भूपेंद्र वरकड़े, जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल

12वीं में रुतुजा को 7वां स्थान.. . .

जिले के चिचोली क्षेत्र के महर्षि दयानंद इंग्लिश स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा ऋतुजा देशपांडे पिता आशीष देशपांडे ने विज्ञान-गणित संकाय में 486 अंक लेकर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7वां स्थान हासिल किया। बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता आशीष देशपांडे पेशे से किसान हैं, जबकि माता माधुरी देशपांडे उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं। ऋतुजा ने भी यह सफलता सेल्फ स्टडी के दम पर प्राप्त की है और वे आगे चलकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं।

अंबेडकर महाविद्यालय में भारत रत्न डॉ. अंबेडकर की जयंती का आयोजन

बैतूल। भीमराव रामराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय बैतूल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के 136 वें जन्मदिवस के अवसर पर जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के संचालक इंजीनियर ध्रुवप्रकाश अग्रवाल की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संचालक ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के जीवन, दर्शन एवं विचारों से प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन एक किताब है और युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। वे भारत के महान विचारक एवं दार्शनिक थे। वरिष्ठ व्याख्याता सुनिल वर्मा ने कहा कि बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर ऐसे समाज को आदर्श मानते थे जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. देशमुख ने कहा कि बाबा साहब ने युवाओं के लिए मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। मनुष्य के बुद्धि का विकास, मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। महाविद्यालय के सभागार में बी.एड. स्कालर्स एवं स्टाफ की उपस्थिति में भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतज्ञ पर आधारित डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन विशाल स्क्रीन पर किया गया।

धूमधाम से मनाया जाएगा भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव

● तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न

बैतूल। बैतूल सनातन समाज बैतूल की बैठक परशुराम मंदिर बडोरा बैतूल में संपन्न हुई। जिसमें ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम जी प्रकट उत्सव 19 अप्रैल, रविवार को धूमधाम से मनाने पर विचार-विमर्श किए गए। सनातन ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष पांडे ने बताया कि 19 अप्रैल को बडोरा मंदिर में सुबह 8 बजे से अभिषेक, हवन-पूजन, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और प्रसादी वितरण शाम 6 बजे से किया जाएगा। उत्सव को लेकर लेकर जिम्मेदारियों भी सौंपी जा रही हैं। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल मिश्र, उपाध्यक्ष राजेश अवस्थी, अनिल दुबे, एस.पाटिल, श्रीमती साक्षी शर्मा, संगीता अवस्थी, आरती अवस्थी नीलम दुबे, मीनाक्षी शुक्ला, श्रीमती पाटिल आदि स्वजातीय बंधु मौजूद थे।

शत-प्रतिशत परिणाम के साथ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल ने मारी बाजी

● अर्पित खंडेलवाल 97 प्रतिशत के साथ रहे अव्वल, ● ब्रज अक्षय पांडे एवं अक्षरा श्रीवास्तव 96 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर ● 81 में से सभी विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण

बैतूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं हाईस्कूल परीक्षा परिणाम में जिले के अग्रणी सीबीएसई स्कूल, सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल किया है और यहां के सभी 81 विद्यार्थी सफल रहे हैं। अर्पित खंडेलवाल ने 97 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं ब्रज अक्षय पांडे और अक्षरा श्रीवास्तव ने 96 प्रतिशत अंक लेकर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पाया। सार्थक ने 95 प्रतिशत अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में यथार्थ पंडागरे ने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि आरुष साहू और वेदिका गोचरे ने 93 प्रतिशत अंक प्राप्त कर क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान प्राप्त किया। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल डायरेक्टर श्रीमती दीपाली निलय डागा और प्राचार्या डॉ. ऋतु वाजपेयी सहित पूरे सतपुड़ा वैली परिवार ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है।

हाईस्कूल परीक्षा में लविजा फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण, माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया

● इंजीनियरिंग में जाना है लक्ष्य

धार। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आज शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के हाईस्कूल के घोषित परिणाम में कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव कमाल फारूकी की पुत्री लविजा फारूकी ने फर्स्ट डिवीजन से पास होकर माता- पिता और स्कूल न्यू तालीम गर्ल्स स्कूल इंदौर का नाम रोशन किया। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही लविजा फारूकी ने बताया कि वह आगे चलकर इंजीनियरिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहती है।लविजा की सफलता पर सभी शुभचिंतकों ने बधाई दी है।

एमपी बोर्ड परीक्षा में जिले का परिणाम शानदार रहा, गत वर्ष की तुलना में सफलता के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी

हायर सेकेन्ड्री में धार जिले की छात्रा अंशिका मजुरिया ने प्रदेश की प्राविण्य सूची में बनाया स्थान

धार। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आज शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इस वर्ष धार जिले का परीक्षा परिणाम न केवल शानदार रहा, बल्कि गत वर्ष की तुलना में सफलता के प्रतिशत में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। हाईस्कूल परीक्षा में जिले के कुल 20,679 नियमित दर्ज परीक्षार्थियों में से 20,505 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 16,242 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए।

सफलता का स्तर- जिले का परीक्षा परिणाम 79.20 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.85 प्रतिशत अधिक है।

श्रेणीवार विवरण- परीक्षा में 10,828 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 5,358 द्वितीय श्रेणी तथा 56 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में सफल रहे।

जिले का परिणाम (79.20 प्रतिशत) राज्य के कुल परिणाम (73.42 प्रतिशत) से बेहतर रहा। हायर सेकेन्ड्री परीक्षा में जिले के कुल 14,049 नियमित दर्ज परीक्षार्थियों में से 14,015 सम्मिलित हुए, जिनमें से 11,298 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष जिले का परिणाम 80.61 प्रतिशत रहा, जो गत वर्ष की तुलना में 8.83 प्रतिशत की बड़ी बढ़त दर्शाता है। हायर सेकेन्ड्री में 8,421 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 2,866 द्वितीय श्रेणी तथा 11 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

अंशिका ने मध्यप्रदेश की प्रावीण्य सूची में आठवां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया - जिले के सादलपुर एकेडमी सादलपुर की छात्रा कुमारी अंशिका मजुरिया ने वाणिज्य संकाय में असाधारण प्रदर्शन करते हुए 500 में से 483 अंक प्राप्त किए हैं। अंशिका ने संपूर्ण मध्यप्रदेश की प्रावीण्य सूची (Merit List) में आठवां स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला धार नरोत्तम वरकडें एवं जिला शिक्षा अधिकारी केशव वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और समर्पित शिक्षक टीम को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य की कामना की है

मां की हत्या कर अंतिम संस्कार करने ले गया बेटा

मोक्षधाम से आरोपी गिरफ्तार, लोहे के पाइप से पीटा

बैतूल। आमला थाना क्षेत्र में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर अंतिम संस्कार का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को मोक्षधाम से गिरफ्तार किया और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार मंगलवार 14 अप्रैल को अंजनी उबनारे, निवासी सौंसर (जिला पांढुर्णा) ने डायल 112 पर सूचना दी कि उसकी बहन शकुंतला गुजरे (62), निवासी बोडखी की शव यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि शव पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही आमला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शकुंतला गुजरे की मौत का कारण खून बहना बताया गया। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और महिला के बेटे दीपांशु गुजरे को आरोपी बनाया। आरोपी के खिलाफ हत्या के मामले में 121/26 और धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बोडखी निवासी आरोपी दीपांशु गुजरे

(32) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दीपांशु ने बताया कि वह शराब का आदी है और पहले भोपाल के नशा मुक्ति केंद्र में भी रह चुका है। करीब एक महीने पहले आमला लौटने के बाद वह अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगता था। घटना वाले दिन मां द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर दीपांशु ने लोहे के पाइप और चप्पल से अपनी मां के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने खून के निशान पानी से साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। वह शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप, चप्पल, मृतिका के कपड़े और चादर जब्त कर ली है। मामले में धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, उप निरीक्षक बलराम यादव सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ग्राम किवलारी में कृषि फीडर बंद, ग्राम रानी पिपरिया में हरिजन बस्ती में बिजली बंद सोहागपुर,पिपरिया में ज्ञापन सौंपे

सोहागपुर । यहां से करीबन 5 किलोमीटर दूर ग्राम किवलारी में क़रीबन 8 अप्रैल से कृषि फीडर बंद पड़ा हुआ है। इससे इससे ग्राम बोदी जर्रन,बांसखापा लांगा बम्होरी, किवलारी एवं बारंगी के किसान परेशान हैं वहीं डीएलएफ बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हुई। किसानों को फसल के लिए निर्बाध बिजली की आवश्यकता है। परन्तु बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।इस संबंध में आज किल्लारी आदि किसानों ने सोहागपुर पहुंच कर उप महाप्रबंधक विधुत विभाग से चर्चा करके ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में राम हजूर पटेल ने बताया कि बिजली के अभाव में किसान परेशान हैं। इस संबंध में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सांसद चौधरी दर्शनसिंह को भी अवगत कराया गया है। वहीं श्री पटेल ने इसी संबंध में विधुत विभाग से जानकारी मांगी है। ताकि किसान सांसद चौधरी दर्शनसिंह को वास्तविकता से अवगत करा सकें। इधर सोहागपुर विधानसभा मुख्यालय के अंतिम छोर पर बसें ग्राम रानी पिपरिया के हरिजन बस्ती के नागरिक बेचारे आन्दोलन के मारे अधिकारियों की तानाशाही से परेशान हैं। हरिजन बस्ती के छोटे-छोटे बच्चे स्कूल के विघार्थी सभी बिजली के अभाव में गांधी के युग में जी रहे हैं। बताया जाता है कि आजकल के अति उपयोगी मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहें हैं। उसको दूसरे मोहल्ले वालों से मिन्नतें करके चार्ज करवा रहे हैं। बिजली की समस्याओं को लेकर आज रानी पिपरिया के ग्रामीणों ने पिपरिया जाकर उप प्रबंधक ग्रामीण विधुत विभाग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन को पढ़कर अधिकारियों को प्रदान किया है। जिसमें अनुरोध है कि ग्राम रानिपिपरिया कि बिजली दिनांक 02 अप्रैल 2026 ने लगातार बंद पड़ी हुई है।आपसे इसके पूर्व भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके अवगत भी करावा गया था । इसके बावजूद भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया ।बंद बिजली होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

मुख्यमंत्री जी सोहागपुर नगर पंचायत स्वच्छता का ढिंढोरा पीट कर प्रचार में ख़र्च कर रही है, स्थिति उससे उलट है

सोहागपुर । मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सोहागपुर नगर पंचायत परिषद स्वच्छता का ढिंढोरा पीट पीट कर प्रचार प्रसार में खर्च कर प्रदेश एवं वरिष्ठ अधिकारियों को जो प्रचार प्रसार में नगर स्वच्छता आईना दिखा रही है। मुख्यमंत्री जी है इससे सब उलट। पूरे नगर के सोशल मीडिया पर आए दिन सफाई व्यवस्था को लेकर नागरिक टिप्पणी डालकर नगर पंचायत परिषद की अकर्मण्यता को उजागर करती रही है। इसके पूर्व नगर में कई बार कांग्रेस एवं एक बार भाजपा की परिषद बनी है। जिसमें यदि सबसे अधिक समय तक रहने वाले पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय एवं पूर्व नपाध्यक्ष शशि संतोष मालवीय की बात करें ।तो संतोष मालवीय प्रातः सुबह 6 बजे से ही नगर का भ्रमण करते निर्माण कार्य एवं सफाई व्यवस्था का जायजा लेते नजर आते थे। उनसे शायद ही कोई वार्ड जायजा लेने से अछूता रहा होगा। इधर जब भाजपा की नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती शीतल मनोज खंडेलवाल बनी ।तब भी भाजपा नेता स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल इधर उधर सफाई व्यवस्था देखते नजर?आते थे। किन्तु इस बार की नगर पंचायत परिषद की कार्यशैली पर प्रारंभ से ही उंगलियां उठने लगी थी। वहीं बार बार सफाईकर्मियों का भुगतान न होने के कारण सफाईकर्मियों ने कई बार सफाई व्यवस्था ठप्प कर दी थी। वहीं सफाई के चार पहिया वाहन भी उम्रदराज हो चुके हैं। इधर सकड़ी गलियों में जाने वाली हाथ ट्रालियां इतनी घटिया निर्माण गुणवत्ता अभाव वाली खरीदी गई थी।कि उनके एक तरफ चक्के चलने को लाचर हो जाते हैं। ठीक है इस्तेमाल के यदि खराब हो जाएं तो उसकी मरम्मत का रास्ता भी है।जिसके मरम्मत करने वाली बीसियों दुकानें हैं। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी। लेकिन आए दिन प्रचार प्रसार पर खर्चा करने के लिए नगर पंचायत परिषद का

जगन्नाथ का हाथ है। अब हम बात करते हैं शास्त्री वार्ड की आंगनवाड़ी की जिसमें पचासों नौनिहाल आते हैं। जिनके खेलकूद एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी गई। लेकिन इस चित्र से अनुमान लगाइए किस कब से हालात दयनीय हैं। जगह जगह-जगह कचरा, जगह-जगह पन्नी पड़ी हुई हैं। दिन रात गायों की डेरा लगा रहता है।इसी आंगनवाड़ी के पास हनुमान मंदिर स्थापित है। लेकिन कैसे कैसे नास्तिक लोग हैं कि संडास की टूटीं हुई शीट मंदिर के पीछे फेंक देते हैं।उनको तनिक भी सांस्कृतिक मर्यादा का आभास नहीं होता। यहां टूटा हुआ नगर पंचायत परिषद का डस्टबिन जो मंदिर के पास लगा था। पड़ा हुआ है। वहीं टूटी नगर पंचायत परिषद की कचरा गाड़ी।आज जब इस प्रतिनिधि यहां का जायजा लिया तो वहां कचरे के ढ़ेर में आग लगी हुई थी। जिससे धुआं निकल रहा था। वहीं तीन चार? गायें फेंकें गए कचरे में पेट की आग बुझाने के खाने की वस्तुएं खोज रहीं। ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी केन्द्र के नौनिहाल कैसे स्वस्थ रहेंगे। बड़ा सवाल है। विगत दिनों भाजपा के सक्रिय सदस्य चिन्टू अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर फोटो सहित लिखा था।कि करीबन 8 महीने में नाली की सफाई हुई है। लेकिन दो दिनों से कचरा वहीं पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर सफ़ाई व्यवस्था चरमराई हुई है।आए दिन अंबेडकर वार्ड के पार्षद एवं पूर्व पार्षद मोहन कहार नगर पालिका अधिकारी से सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था की गुहार लगाते रहते हैं। इस संबंध में पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय ने ध्यानाकर्षण करते हुए बताया कि जगह-जगह सफाई व्यवस्था अपना रोना रो रही है।केवल दो तीन वार्डों को छोड़कर पूरे सोहागपुर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है हमारे समय में 15 मैजिक वाहन थे। वो वाहन कहां गुमनामी में चले गए हैं। उनका क्या हुआ यह बड़ा सवाल है। न तो सफाई हो रही है।न ही कर्मचारियों के पास कचरा उठाने की ट्रालियां है। आपने आरोप लगाया कि इतनी सारी ट्रालियां , मैजिक वाहन कहां चले गए । करीबन तीन दिन पहले मस्जिद के पास वाली साफ हुई। जिसका निकला अभी तक पड़ा हुआ है। आपने कहा सफ़ाई की बात तो छोड़िए सारे नगर की नालियां ओवर फिलो हो रहीं हैं। बताया जाता है कि हाल ही में नगर पंचायत परिषद ने चार मैजिक वाहनों को फिर आठ आठ लाख रुपए में खरीदे है। पुराने वाहन वाहनों का अता-पता नहीं है। इधर चर्चा में पता चला है कि वाहन कम चल रहे हैं। फिर भी डीजल की खपत दिन दूनी रात चौगुनी की तरह खपत हो रही है। आखिर ये नगर पंचायत परिषद का डीजल कहां खप हो रहा है?। जेसीबी मशीन में भी डीजल सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है।किन वाहनों में इसका उपयोग किया जा रहा है?। कितना खर्च होना चाहिए इसका अंकेक्षण नगरीय निकाय प्रशासन को करना चाहिए। तभी दूध का दूध पानी का पानी अलग-अलग हो जाएगा।उधर वाटिका ग्रार्डन परिसर के निकटवर्ती स्कूल के सामने बीसियों दिनों से नगर पंचायत परिषद की अकर्मण्यता के कारण निरंतर गंदा पानी बह रहा है। जिससे पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग पर गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। परन्तु नगर पंचायत परिषद आंखों बंद करके सो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों नागरिक कह रहे थे कि इससे पहले ऐसी नगर पंचायत परिषद अस्तित्व में नहीं आई थी।यह वह रास्ता है जो विश्व विख्यात पर्यटन पचमढ़ी जाने वाला रास्ता है। देश विदेश के पर्यटक सोहागपुर नगर पंचायत परिषद की कितनी ख्याति करेंगे।सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि कि आगामी नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता-जनार्दन चुनेंगी। जनता पूरे कार्यकाल का लेखा-जोखा देखकर ही नगर परिषद चुनती है।नगर पंचायत परिषद के क्रियाकलापों के कारण आगामी चुनाव में अध्यक्षीय चुनाव जीतना भाजपा के लिए दूर की कोड़ी सिद्ध होगी ?।

पेयजल संकट के समाधान को प्राथमिकता

जनप्रतिनिधि-प्रशासन की संयुक्त बैठक में विकास, पेयजल, सिंचाई और लैंडबैंक विस्तार पर व्यापक चर्चा

● नल-जल योजनाओं को गुणवत्ता और समयसीमा पर पूर्ण करने के सख्त निर्देश

बैतूल, (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तियां उईके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य श्री सुधाकर पवार तथा कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पेयजल प्रबंधन, नल-जल योजनाओं की प्रगति, सिंचाई परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट को प्रमुखता से लेते हुए मंत्री श्रीमती उईके ने निर्देश दिए कि नल-जल योजनाओं के शेष कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि पूर्ण योजनाओं को विधिवत सत्यापन के बाद पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा उनके रखरखाव में तकनीकी सहयोग पीएचई विभाग द्वारा दिया जाए। साथ ही सड़क रेस्टोरेशन कार्य भी समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जिले के कई क्षेत्रों में जलस्तर गिरने से पेयजल संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे सभी गांवों में प्राथमिकता के आधार पर हैंडपंप एवं ट्यूबवेल निर्माण कराया जाए। उन्होंने पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश भी दिए, जिसमें प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बैठक में जल निगम अंतर्गत समूह नल-जल योजनाओं में गति लाने, ठेकेदारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करने तथा लापरवाही पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले के लिए ढहकना वृहद परियोजना स्वीकृत की गई है, जिससे आठनेर, भीमपुर, चिचोली और शाहपुर क्षेत्रों के गांव लाभान्वित होंगे। साथ ही घोघरी परियोजना से लाभान्वित गांवों का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए गए। विकास को गति देने के लिए विधायक श्री खंडेलवाल ने जिले में लैंडबैंक बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि वन विभाग और प्रशासन के समन्वय से लैंड बैंक का चिन्हांकन कर उद्योग, डैम, मंडी और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। ताप्ती कंजर्वेशन फॉरेस्ट में बटरफ्लाई पार्क, ग्रासलैंड विकास एवं होमस्टे जैसी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। बैठक में विभिन्न विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी उठाईं। आमला और मुलताई क्षेत्र में बैराज निर्माण, घोड़ाडोंगरी में सुखी नदी पर बैराज, भैंसदेही में मेडा जलाशय प्रभावितों के मुआवजे तथा गन्ना किसानों के पंजीयन संबंधी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। नगरीय प्रशासन की समीक्षा करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही अतिक्रमण हटाने के बाद स्थायी चिन्हांकन सुनिश्चित करने को कहा गया। वन विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रकरणों, वन विस्थापन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सभी स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने तथा सड़कों के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि विकास कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जिले को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।

हर पंचायत में पलायन का रिकॉर्ड रखें, बच्चों की शिक्षा पर रखें विशेष नजर - कलेक्टर

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा

कि जिले की प्रत्येक पंचायत में पलायन करने वाले परिवारों की विस्तृत सूची संधारित की जाए, जिससे उनके आवागमन और स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी परिवार गांव को कब छोड़कर गया और कब वापस लौटा, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो। साथ ही इस अवधि के दौरान उनके बच्चों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए कि वे स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित रहे या नहीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा एवं पोषण प्रभावित न हो, इसके लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर ऐसे बच्चों की नियमित ट्रैकिंग करें और आवश्यकतानुसार विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के साथ अमल में लाएं तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर प्रगति से अवगत कराएं।

उपार्जन केंद्र रुसल्ली में सीसीबी सीईओ का निरीक्षण, स्व-सहायता समूहों से की चर्चा

विदिशा,(निप्र)। लटेरी जनपद के उपार्जन केंद्र रुसल्ली में सीसीबी के सीईओ श्री विनय द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने

केंद्र पर चल रही उपार्जन व्यवस्था, किसानों को मिल रही सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान सीईओ श्री विनय ने केंद्र पर उपस्थित स्व-सहायता समूह (SHG) की महिलाओं से भी चर्चा की। उन्होंने समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों, उनकी भूमिका एवं उपार्जन प्रक्रिया में सहभागिता के बारे में जानकारी ली। साथ ही समूहों को बेहतर समन्वय एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। तौल, भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाएं समयबद्ध एवं सुचारु रूप से संचालित हों, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं स्व-सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं।

शासकीय आईटीआई में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 36 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन

विदिशा,(निप्र)। शासकीय आईटीआई विदिशा और जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज सोमवार को शासकीय आईटीआई विदिशा में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। आईटीआई प्राचार्य सुश्री कविता रघुवंशी ने बताया कि इस प्लेसमेंट

ड्राइव में वैमेंट इंडिया लिमिटेड दर्ज, वॉल्वो आईसर भोपाल, एक्सिस बैंक सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने भाग लिया एवं उनके द्वारा योग्यता अनुरूप इच्छुक युवक-युवतियों का चयन विभिन्न पदों हेतु किया गया है। इस प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 96 आवेदकों द्वारा पंजीयन किए गए थे जिसमे से कुल 36 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन किया गया है। वैमेंट कंपनी के फाइनल चयन का राउंड ऑनलाइन वीडियो कॉल द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत चयन की सूची एवं ऑफर लेटर प्रदाय किए जाएंगे।

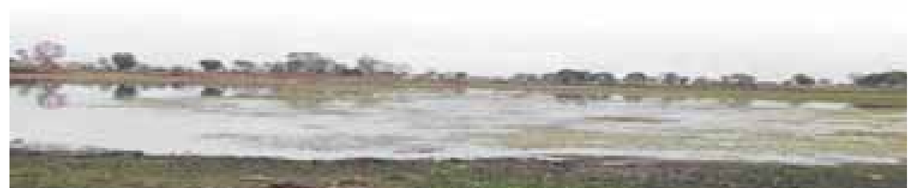

कुरवाई में तालाबों से अतिक्रमण हटाकर जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल, पांच तालाब मुक्त

विदिशा, (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन एवं एसडीएम श्री मनीष जैन के कुशल निर्देशन में कुरवाई अनुभाग में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विभिन्न गांवों में स्थित तालाबों से अवैध अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। अभियान के तहत अब तक गिरवासा, कर्मोदिया, घोसुआ, बरवाई एवं बर्री सहित कुल 5 तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया है। इन तालाबों पर लंबे समय से अवैध रूप से खेती की जा रही थी। स्थानीय प्रशासन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह कार्रवाई शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरीके से पूरी की गई। एसडीएम श्री मनीष जैन ने बताया कि तालाब ग्रामीण जीवन, भू-जल स्तर बनाए रखने एवं जैव-विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि तालाबों पर अतिक्रमण न केवल जल संकट को बढ़ावा देता है, बल्कि आपदा के समय जल निकासी में भी बाधा उत्पन्न करता है। प्रशासन भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। अतिक्रमण मुक्त कराए गए तालाबों में अब गहरीकरण, सफाई एवं सौंदर्यीकरण के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे तालाबों एवं अन्य सार्वजनिक जल स्त्रोतों पर अतिक्रमण न करें तथा कहीं भी अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर तुरंत राजस्व विभाग या स्थानीय पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सांची पार्लर का किया शुभारंभ

कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित अन्य नागरिकों को मिलेगी सुविधा

नर्मदापुरम, (निप्र)। कलेक्टर सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सांची पार्लर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्लर में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों एवं सामग्रियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उद्घाटन के दौरान कलेक्टर ने पार्लर संचालक श्री अरविंद को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठान के शुरू होने से कलेक्ट्रेट में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित अन्य नागरिकों को सुविधा मिलेगी। अब उन्हें सांची के उत्पाद आसानी से कार्यालय परिसर में ही उपलब्ध हो सकेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर ने पार्लर से प्रथम खरीदी भी की और वहां कार्यरत कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पार्लर सभी के लिए उपयोगी साबित होगा तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के अंतर्गत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कार्यक्रम आयोजित

सीहोर, (निप्र)। नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के अंतर्गत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नारी सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना तथा समाज में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान को समझाना था।

● दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किया गया जागरूक - पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दहेज जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम में सहयोग करने के लिए जागरूक किया गया।

सशक्त नारी, समृद्ध भारत
महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति बैठक में सांसद माया नारोलिया ने साझा किए विचार

नर्मदापुरम, (निप्र)। नर्मदापुरम भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति के अध्ययन दौरे (स्टडी विजिट) के तहत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं के अधिकारों एवं उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी। बैठक के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

दौरे के प्रथम दिन दो प्रमुख सत्रों में हुआ मंथन

● **प्रथम सत्र :** इस सत्र में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। चर्चा का मुख्य केंद्र महिलाओं को कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाना रहा।

● **द्वितीय सत्र (सुरक्षा और अधिकार):** दूसरे सत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और POSH Act 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

इसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, एनएफएल, आरसीएफएल सहित बैंकिंग क्षेत्र से बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सांसद माया नारोलिया ने इस अवसर पर कहा कि यह अध्ययन भ्रमण महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सशक्त भूमिका दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नारी शक्ति' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए इस प्रकार के नीतिगत विचार-विमर्श और प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 3 वाहनों को किया जप्त

बैतूल, (निप्र)। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, उत्खनन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खनिज विभाग ने विगत 3 दिनों में खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौण खनिजों के अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2026 को तहसील आमला क्षेत्रांतर्गत ग्राम तोरणवाड़ा के समीप से खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन ट्रेक्टर एमपी 48 ए 3677 एवं घिसी बोरी मार्ग के समीप से 01 वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 48 एए 9017 को जप्त कर पुलिस थाना आमला की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।

जनगणना 2027 की तैयारियां हुई तेज, जिले में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ

नर्मदापुरम,(निप्र)। नर्मदापुरम जिले में जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। इसी क्रम में माखननगर, शिवपुर, सिवनी मालवा एवं नर्मदापुरम नगर में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन लगभग 450 प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ये सभी प्रशिक्षित प्रगणक 1 से 30 मई तक चलने वाले जनगणना कार्य के अंतर्गत घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के विभिन्न चार्ज क्षेत्रों में 3-3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक टीम को तीन दिनों का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) ऐप के उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

चयनित ग्रामों में निर्माण एवं विकास के कार्य व्यवहारिक और सर्वथा उपयोगी हों - कलेक्टर

पीएम आदर्श ग्राम योजना में शामिल हैं सीहोर जिले के 29 गांव

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला अभिसरण समिति की बैठक आयोजित

सीहोर, (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के ने कहा कि योजना के अंतर्गत चयनित सभी ग्रामों में निर्माण विकास के कार्य व्यवहारिक और सर्वथा उपयोगी हों। उन्होंने कहा की गावों की आवश्यकताओं और उपयोग को ध्यान में रखकर कार्यों का निर्धारण करें, ताकि इस योजना का उद्देश्य सार्थक हो सके। उन्होंने चयनित ग्रामों में संचालित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं की

उपलब्धता, प्रस्तावित कार्यों तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए ग्रामों के समग्र विकास को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है, जिसके लिए आवश्यक है कि सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कार्यों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग करें तथा ग्रामों में विकास कार्यों को गति प्रदान करें, ताकि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

योजना में सीहोर जिले के 29 ग्राम शामिल

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के 29 ग्रामों को शामिल किया गया है, जिनमें आष्टा के 17, सीहोर के 05, इछावर के 05, बुधनी का एक और भैरूंदा का एक गांव शामिल है। चयनित ग्रामों की बात करें तो योजना में ग्राम कान्याखेडी, भानाखेडी, पटारिया चौहान, देवनखेडी, खेनियापुरा, भाऊखेडा, नवरंगपुर, गाजना, जताखेडा, भेरूपुर, ईसईलखेडी, परोलिया, बुरानाखेडी, लच्छीरामजीपुरा, पागरी, शोभाखेडी, अरनिया दाउद, बिजौरा, रामपलासी, डेंडी, तोरनिया, खारपा, कुल्हाडी, लसुडिया गौंडी, जाटखेडी, हिमतपुरा, लसुडिया शेखु, सनखेडी और श्यामुगांव शामिल है।

राइट क्लिक

भाजपा के राज्यों में सत्ता संधान के अभिनव फंडे...!

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क- 9893699939
ajaybokil@gmail.com

बिहार में जिस नफीस अंदाज में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कथित स्वैच्छिक राजनीतिक वानप्रस्थ में भेजा गया और उनकी जगह सीएम के रूप में भाजपा के सम्राट का राज्याभिषेक किया गया, वह भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्यारोहण का चौथा और नवीनतम महाप्रयोग है। इस मायने में आज देश में भाजपा का कोई भी सियासी सानी नहीं है, जिसने सत्ता संधान के इतने विविध तरीके ईजाद किए हों। इसके पहले दलबदल ही पिछले दरवाजे से सत्तासीन होने का एक मात्र फंडा था। जबकि भाजपा के इन फंडों में दबाव, दबंगई, धैर्य, चतुराई, उग्रता, सौम्यता, मित्रता, शत्रुता, अवसरवाद और दीर्घकालीन लक्ष्य सामने रखकर हाईब्रिड चालें चलते रहना भी शामिल है।

राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इन चालों को बारीकी से देखें तो भाजपा ने हर उस राज्य में, जहां वह केवल अपने दम पर सत्ता हासिल करने की स्थिति में नहीं है, और जहां अन्य क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के बगैर उसका आगे बढ़ना संभव नहीं है या फिर उन राज्यों में जहां जनसांख्यिकी और जातिवाद का अलग स्ट्रक्चर है, सत्ता में आने के लिए अलग-अलग मॉडल विकसित किए हैं। बिहार इस मॉडल श्रृंखला का चौथा 'सफल' प्रयोग है। संभव है कि हमे इसका एक और नया प्रयोग पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव में भाजपा यूं तो अपने दम पर सत्ता पाने के और ममता बैनर्जी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन खुदा-न-खास्ता किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला तो वहां भी कोई नया 'खेला' देखने को मिल सकता है।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के तीन मान्य तरीके रहे हैं। पहला, कोई भी पार्टी चुनाव जीतकर बहुमत के साथ अपने दम पर सत्ता में आ जाए। इस हिसाब से आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा है, किसी सत्तासीन या क्षेत्रीय दल की सत्ता को दल-बदल कर गिरा दिया जाए और हर मुमकिन जोड़तोड़ कर अपनी सरकार बनाई जाए, जैसे कि मध्यप्रदेश में 6 साल पहले हुआ। तीसरा, महाराष्ट्र मॉडल है, जहां पहले किसी सहयोगी दल का सीएम बनकर भाजपा उसे कंधा दे और चुनाव करवाकर खुद उसके कंधे पर सवार हो जाए। चौथा है, बिहार मॉडल। जहां सियासी हालात को अपने अनुकूल ढलने तक का लंबा इंतजार किया जाए और कंधा देते-देते धीरे से सवार को उतारकर खुद पालकी में विराजमान हुआ जाए और यह सब कुछ लखनवी नफासत के साथ किया जाए कि कोई उफ् तक न कर सके और इसे नियति का चक्र मानकर खुद हाथ में झांझ-मंजीरे थाम बैठे। हालांकि यह मॉडल मप्र मॉडल के ठीक विपरीत है, जहां भाजपा ने मामूली बहुमत से सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार में ही सेंध लगा दी और पार्टी की अंतर्कलह को अपने पक्ष में भुना लिया। या यूं कहे कि मोटे तौर पर पहले ही भगवा रंग में रंग चुके मप्र में सत्ता संचालन में आया यह मामूली 'ब्रेक' था, जिसे सियासी हिकमत के साथ 'ठीक' कर लिया गया। इस दृष्टि से भाजपा में 'हिकमत' शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। इसमे 'साम-दाम-दंड-भेद' सब जायज है और इस राजनीतिक नैतिकता के पैमाने भी 21वीं सदी की भाजपा के हैं। इसके आगे दूसरी राजनीतिक पार्टियां लगभग बेबस नजर आती हैं। उनके सामने दो ही विकल्प हैं। या तो वो भाजपा के साथ, उसकी शर्तों पर उसके दास बनकर रह लें या फिर सत्ता गंवाने के लिए तैयार रहें। चूंकि राजनीति का अंतिम ध्येय सत्ता है और वो कैसे हासिल की जाती है, यह सवाल नैतिक होते हुए भी अदम्य सत्ताकांक्षा के आगे गौण है। भाजपा का इसमे पूरा विश्वास है।

इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब भाजपा के कोर एजेंडे के सभी मुद्दे पूरे हो चुके हैं। इसलिए सत्ता संधान के लिए नया धनुष और बाण चाहिए। भाजपा अंतिम कोर मुद्दा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का है, जिसे उसने अलग तरीके से राज्यवार लागू करना शुरू किया है। संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के एजेंडे पूरे हो ही चुके हैं। यानी इनके बूते अब मतों के दोहन की संभावना नहीं के बराबर है। इन भावनात्मक मुद्दों से हटकर पार्टी महिलाओं को सीधे नकदी जैसे तरीकों को आजमा रही है, जो जमीनी स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा फलदायी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये उपाय सत्ता परिवर्तन के पुराने फंडे से प्रेरित हैं कि जनादेश हासिल कर सत्ता में आया जाए और फिर इसी के सहारे अंगद के पांव की तरह जमा जाए। हालांकि इस काम में विकास, हिंदुत्व, समान अधिकार, सुशासन, समरसता आदि अनुषांगिक घटक हैं।

जहां तक बिहार की बात है तो वहां सत्ता सीधे अपने हाथ में लेने के लिए भाजपा ने माफिक गजब का धैर्य दिखाया है। देर से ही सही, वह घड़ी आ गई कि पटना में घी के दीए जलाए जाएं। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के राज में ज्यादातर समय भाजपा के सहारे ही राजनीति की और सुशासन बाबू की छवि गढ़ी। क्योंकि लालू राज में बिहार गवर्नेंस के पाताल में चला गया था। ऐसे में वहां के लोगों को नीतीश कुमार का 'सुशासन' भी राम राज की तरह लगने लगा।

यह बात अलग है कि नीति आयोग के विकास के तमाम पैमानों पर बिहार आज भी सबसे निचली पायदान पर है। विकास की दौड़ में यूपी और एमपी भी उससे काफी आगे निकल गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह उस राज्य की हालत है, जिसे देश का सर्वाधिक राजनीतिक चेतना वाला प्रदेश कहा जाता है। वहां से कई क्रांतिकारी आंदोलन उठे। इन आंदोलनों ने दूसरे राज्यों को तो बदल दिया, लेकिन 'दिया तले अंधेरे' की तर्ज पर बिहार जहां का तहां रहा। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि वहां इस मुखर राजनीतिक चेतना की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की चेतना से आदर्श जुगलबंदी कभी भी नहीं हो सकी। बहरहाल, राज्य के नए और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी यह जुगलबंदी आगे हो सकेगी या नहीं, कहना मुश्किल है। बताया यही जा रहा है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की भी पसंद हैं, क्योंकि वह अति पिछड़ी कोइरी जाति से आते हैं। लेकिन इस 'जातीय फिक्स्ड डिपॉजिट' से कोई बुनियादी मसला हल नहीं होता। सम्राट अपनी जातीय पूंजी को राज्य के विकास में कैसे निवेश करते हैं, यह देखने की बात है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राज्य में डबल इंजिन की सरकार बनने से विकास की गति और दिशा तेज होगी। लेकिन खतरा यह भी है कि बिहार में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है। सम्राट चौधरी इस पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, यह भी देखना होगा। वैसे सम्राट को स्वीकारने में बिहार के सभी समुदायों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री भले हों, लेकिन वो संघ की पाठशाला के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट भी एक दीर्घ कालीन एजेंडे के तहत तात्कालिक व्यवस्था है। इस 'सम्राट' को भी दिल्ली के तख्त का हुकुम ही मानना होगा और भाजपा का खांटी राष्ट्रवादी नेतृत्व तैयार होने तक राज्य का रथ हांकना होगा। वैसे भी बिहार से नीतीश की विदाई मंडलवाद, समन्वयवाद, राजनीतिक हिंडोलावाद (कभी इधर तो कभी उधर), अति पिछड़ावाद और सियासी सौम्यता की भी विदाई है। अब देखना यह है कि बिहार किस राज्य को फॉलो करता है, यूपी को, गुजरात को, मप्र को अथवा असम को। आगे की सियासत यह भी तय करेगी कि भाजपा सत्ता में आने अथवा बने रहने का कोई चौथा फार्मूला भी विकसित करेगी या नहीं।

संघ शाखा में डॉ. अम्बेडकर ने किया सामाजिक समरसता का अनुभव : अशोक पांडेय

भोपाल। विश्व संवाद केंद्र, मध्यप्रदेश की ओर से सामाजिक समरसता के अग्रदूत भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉ. अंबेडकर विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उनके विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्यभारत प्रांत के प्रांत संघचालक अशोक पांडे ने ऐतिहासिक संदर्भों के साथ अपने विचार रखते हुए बताया कि 2 जनवरी 1940 को सतारा के कराड में डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गए थे और वहां उन्होंने सामाजिक समरसता का अनुभव किया। 'केसरी' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार, डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ बातों से असहमति हो सकती है, लेकिन संघ के काम की मैं सराहना करता हूँ। पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में भी डॉ अंबेडकर शामिल हुए। वहां उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक सामाजिक समरसता के साथ रह रहे हैं। 1949 में संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी और डॉ. अम्बेडकर की भेंट का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि केशव बलिराम हेडगेवार ने 1920 में ही शोषणमुक्त समाज की अवधारणा प्रस्तुत कर दी थी। पांडेजी ने स्पष्ट किया कि कानून के माध्यम से समता स्थापित की जा सकती है, लेकिन समरसता केवल आत्मीयता और बंधुत्व के भाव से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा कि 1963 में माधव सदाशिव गोलवलकर के मार्गदर्शन में समरसता का जो संदेश समाज के सामने आया और जिसे आगे बालासाहब देवरस ने विस्तार दिया, उसकी प्रेरणा डॉ. अंबेडकर के विचारों से ही जुड़ी हुई है। मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के पूर्व कुलाधिपति तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रकाश बरतूनिया ने कहा कि अंबेडकर ने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय इतिहास एवं दर्शन को आत्मसात किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके विचारों में भारतीय जीवन मूल्यों की स्पष्ट झलक मिलती है।

भोपाल की सान्वी को 99.8 प्रतिशत, सागर की प्रांशी को 98.2 प्रतिशत अंक

भोपाल (नप्र)। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in और उमंग ऐप पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। भोपाल रीजन में इस साल 10वीं की परीक्षा के लिए 1 लाख 15 हजार 889 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा के परिणामों में डीपीएस भोपाल की सान्वी झा ने भोपाल क्षेत्र से 99.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सागर पब्लिक स्कूल की प्रांशी तिवारी ने 98.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जवाहरलाल नेहरु स्कूल के सोहम राजपूत ने 10वीं में 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी- सीबीएसई बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। इसके अलावा रिजल्ट में कोई टॉपर भी घोषित नहीं किया जाता है। बोर्ड सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश भी देता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल या जिले का टॉपर घोषित न करें।

एमपी बोर्ड टॉप-10 में रिकॉर्ड 378 स्टूडेंट्स, बेटियां फिर आगे- मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार 73.42 प्रतिशत रेगुलर छात्र पास हुए। टॉप टेन में 378 स्टूडेंट्स शामिल हैं। इन्होंने 490 से 499 तक नंबर हासिल किए। टॉप-5 में ही 39 विद्यार्थी शामिल रहे।

पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया- पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर 498 नंबर वाले दो स्टूडेंट (बालाघाट की अक्षरा घोडेश्वर और सीधी के अभय गुप्ता) हैं। तीसरे नंबर पर सात छात्र रहे। इन्होंने 497 अंक हासिल किए।12 छात्र चौथे नंबर पर रहे। सभी ने 496 नंबर हासिल किए। 17 छात्र पांच नंबर पर रहे। इन्होंने 495 अंक हासिल किए। 342 स्टूडेंट्स के नंबर 490 से 494 के बीच हैं।